सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.parivahanvishesh.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

ऊँचाई पर वही पहुँचते है, जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते है।

वर्ष 01, अंक 205, नई दिल्ली

शनिवार, 07 अक्टूबर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

मेट्रो फेज-3 प्रोजेक्ट की कवायद शुरू, डीएमआरसी ने डीपीआर के लिए जीडीए से मांगे 10 लाख

- प्रभारी मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है। जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। मालूम हो, कि वर्ष 2020 में डीएमआरसी ने नोएडा सेक्टर-62 से वसुंधरा कट तक मेट्रो प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की थी।

संजय बाटला

मेट्रो फेज-3 प्रोजेक्ट नोएडा सेक्टर-62 से रैपिडएक्स ट्रेन के साहिबाबाद स्टेशन तक मेट्रो चलाने के लिए एक बार फिर से कवायद शुरू हुई है। मेट्रो फेज-3 प्रोजेक्ट की संशोधित डीपीआर तैयार करने के लिए डीएमआरसी ने जीडीए से 10 लाख रुपये मांगे हैं। इसके अलावा पुराने बकाये के 23 लाख रुपये के भुगतान करने के लिए भी कहा है।

नईदिल्ली/गाजियाबाद। मेट्रो फेज-3 प्रोजेक्ट नोएडा सेक्टर-62 से रैपिडएक्स ट्रेन के साहिबाबाद स्टेशन तक मेट्रो चलाने के लिए एक बार फिर से कवायद शुरू हुई है। मेट्रो फेज-3 प्रोजेक्ट की संशोधित डीपीआर तैयार करने के लिए डीएमआरसी ने जीडीए से 10 लाख रुपये मांगे हैं।

DMRC ने पुराना भुगतान भी मांगा

इसके अलावा पुराने बकाये के 23 लाख रुपये के भुगतान करने के लिए भी कहा है। प्रभारी मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है। जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। मालूम हो, कि वर्ष 2020 में डीएमआरसी ने नोएडा सेक्टर-62 से वसुंधरा कट तक मेट्रो प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की थी।

मेट्रो प्रोजेक्ट में आएगी 1517 करोड़ की लागत

5.017 लंबे रूट पर मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत उस वक्त 1517 करोड़ रुपये प्रस्तावित थी। अब, क्योंकि वसुंधरा कट से आगे बढ़ाकर मेट्रो को रैपिडएक्स के साहिबाबाद स्टेशन से जोड़ने की योजना है। इसीलिए डीपीआर में थोड़ा संशोधन होना है। पुराने डीपीआर में थोड़ा संशोधन कर रैपिडएक्स के साहिबाबाद स्टेशन तक रूट को बढ़ाया जाएगा।

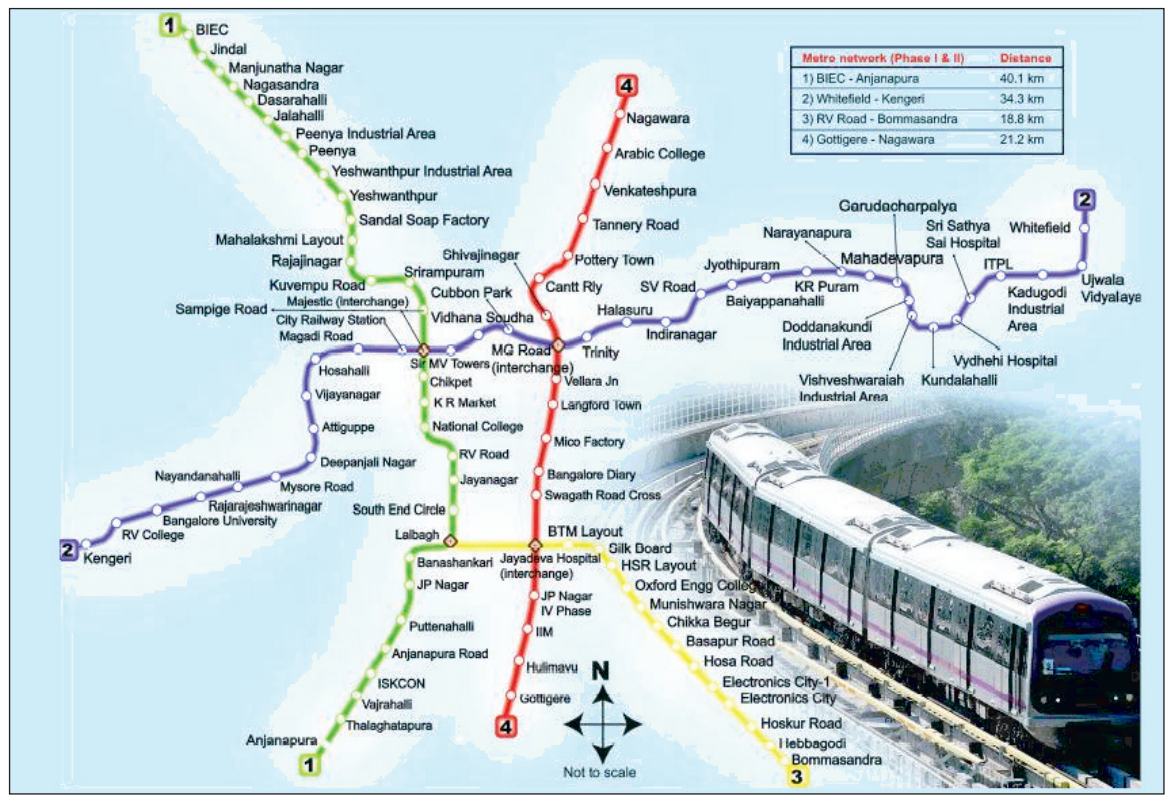

advertisement Tariff
w.ef. 1st January 2023

परिवहन विशेष
दिल्ली, एनसीआर से प्रसारित लोकप्रिय साप्ताहिक हिन्दी समाचार पत्र

in Rs. / Sq. Cm.

	Basic	3rd Page	Back Page	Front Page Semi Solus	Font Page Solus
Delhi Aur Delhi	BW - Colour	Colour	Colour	Colour	Colour
Delhi	100*	200*	250*	300	300

Special Instructions:-
- Innovation on any page will be accepted at a premium of 100% on applicable card rate.
- Any specified position will be accepted at a premium of 25% on applicable card rate.
- B/W advertisement on page 3/back will charged at colour rate.
- Classified display advertisement will be charged on basic display rate.
- Pointers 4x4 sq. C. or 5x4 sq. cm. will be charged as per card rate.
- box reply charges (each box) will be charged Rs. 150/-
- Political advertisement - as applicable.

परिवहन विशेष में विज्ञापन के लिए ऑनलाईन भुगतान सीधे बैंक खाते/फ़ोन पे पर कर सकते हैं और विज्ञापन के मैटर के साथ ऑनलाईन भुगतान की रसीद व्हाट्सऐप नंबर 09212122095 या newstransportvishesh@gmail.com पर भेज सकते है। भुगतान करने के लिए *NEFT / IMPS / RTGS*
Account Name:-Transport Vishesh Limited
IFSC CODE :- INDB0001396
Cur Account no :- 259212122095
या Phone pay :- 9212122095

इस देश में मनमर्जी से नहीं खरीद सकते कार , पहले लेना पड़ता है 60 लाख रुपये का यह सर्टिफिकेट

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में आपको कोई नया वाहन खरीदना हो तो आप सिर्फ शोरूम में जाकर, अपने पसंदीदा मॉडल को चुनकर, उसकी कीमत अदाकर, अगर कार उपलब्ध है तो लेकर घर जा सकते हैं। लेकिन सिंगापुर में आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं।

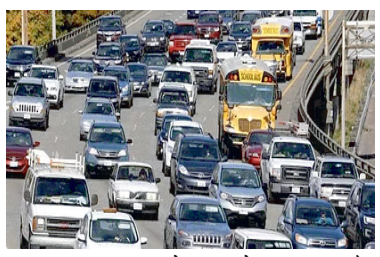

सिंगापुर में नई कार खरीदना आसान नहीं है। भारत में आपको कोई नया वाहन खरीदना हो तो आप सिर्फ शोरूम में जाकर, अपने पसंदीदा मॉडल को चुनकर, उसकी कीमत अदाकर, अगर कार उपलब्ध है तो लेकर घर जा सकते हैं। लेकिन सिंगापुर में आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। इस छोटे से द्वीप राष्ट्र के पास सीमित जगह है और इसने हमेशा सार्वजनिक परिवहन विकल्पों को लोकप्रिय बनाने को प्राथमिकता दी है। वास्तव में, जो कोई भी नई कार खरीदना चाहता है, उसे पहले एंटाइटेलमेंट सर्टिफिकेट (सीओई) लेना पड़ता है, जो 1990 से लागू है। लेकिन हाल ही में, सीओई हासिल करने की लागत बढ़ गई है।

सीओई अनिवार्य रूप से एक बोली प्रक्रिया है जो सिंगापुर के किसी निवासी को 10 साल की अवधि के लिए कार चलाने का अधिकार देती है। वाहनों की श्रेणियां सूचीबद्ध हैं और हर श्रेणी में सीमित संख्या में उपलब्ध कोटा हैं। तुलनात्मक रूप से महंगी कीमतों के बावजूद, स्थानीय लोगों की संख्या लगभग हमेशा इससे ज्यादा रही है। सीओई लागत में भारी बढ़ोतरी के बावजूद, यहां लेटेस्ट दौर के लिए भी यह सच है।

सबसे किफायती सबसे निचली श्रेणी या कैटेगरी ए है। इस कैटेगरी में 1.6 लीटर तक की इंजन क्षमता या 130 एचपी तक के पावर आउटपुट वाले वाहन होते हैं। सीओई की लागत 104,000 सिंगापुरी डॉलर या लगभग 60 लाख रुपये है। बड़े वाहनों के लिए, जिनकी इंजन क्षमता 1.6 लीटर से ज्यादा या पावर आउटपुट 130 एचपी से अधिक है, सीओई की लागत अब 146,002 सिंगापुरी डॉलर या लगभग 88 लाख रुपये है। ऐसे देश में जहां औसत वार्षिक आय लगभग 70,000 सिंगापुरी डॉलर या लगभग 42 लाख रुपये है, सीओई लागत वास्तव में बहुत ज्यादा है। लेकिन चूंकि कोटा संख्या अपेक्षाकृत छोटी है - ज्यादातर श्रेणियों के लिए कम सैकड़ों में, बोलियां लगभग हमेशा उपलब्ध स्लॉट से ज्यादा होती हैं।

प्रदूषण की आड़ में प्राइवेट/कॉर्मिशयल डीजल की BS4 की कारों/टैक्सीयों और टेम्पो ट्रेवलर को बंद करने के खिलाफ दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की मीटिंग आयोजित

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में आने वाले महीनों में प्रदूषण की आड़ में प्राइवेट /कमर्सयल डीजल की BS 4 की कारो /टैक्सीयों और टेम्पो ट्रेवलर को बंद करने के खिलाफ आज दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल, गुरुद्वारा रकाबगंज गुरुद्वारा में हुई.

ट्रांसपोर्टस एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है की कमिसन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की सिफाराश पर जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से ऊपर होगा, दिल्ली एनसीआर में सारी पेट्रोल की BS 3 प्राइवेट कारे और डीजल की BS 4 टूरिस्ट टेम्पो ट्रेवलर और टैक्सी बंद कर दी जाएंगी (4 पहिये की सारी गाड़ियाँ) पिछले साल ये सारी गाड़ियाँ दिल्ली में ही बंद करी थी, क्योंकि पिछले साल दिल्ली में सिर्फ हमारी एसोसिएशन ने ही इसका विरोध करा था, और किसी ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने नहीं, इसकी वजह से सरकार और CAQM की हिम्मत और बढ़ गई और इस बार पूरे एनसीआर में YE गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा.

डीजल BS 4 बसों के बारे में अभी घूमहराहा करा जा रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार और CAQM नहीं चाहते की अभी से ट्रांसपोर्टर्स कोई आंदोलन ना छेड दें.

संजय सम्राट का कहना है की ये सारा मामला प्रदूषण का है ही नहीं. क्योंकि स्टेज 3 में ये सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल को बंद कर रहें है, लेकिन डीजल BS 4 ट्रको को खुला चलने की इज्जाजत दें रहें है.

संजय सम्राट का कहना है की डीजल बसों के मुद्दे पर वो CAQM के चेयरमैन से मिले थे तब CAQM के चेयरमैन ने कहा था की वो दुसरे राज्यों की डीजल BS 4 बसें दिल्ली एनसीआर में प्रवेश नहीं करने देंगे 1 नवम्बर 2023 से या इस से पेहले भी अगर प्रदूषण बढ़ जाएगा तो.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है की ये सारा खेल BS 6 की पेट्रोल /डीजल की गाड़ियों को बेचने का है, साथ ही महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बेचने का भी. क्योंकि जब BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल गाड़ियाँ सरकार बंद करेंगी तब ही लोग दूसरी इलेक्ट्रिक और BS 6 डीजल /पेट्रोल की गाड़ियों को खरीदेंगे.

आज ट्रांसपोर्टर्स ने तय किया है की अगर प्रदूषण के नाम पर उनकी BS 4 टूरिस्ट टैक्सी -बसों और टेम्पो ट्रेवलर को बंद किया तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे.

सब ट्रांसपोर्टर्स का कहना है की सरकारे उनकी खून पसीने की कमाई को कबाड़ में बदलना चाहता है. जल्द ही इस बारे में

प्रधानमंत्री जी और उप राजयपाल को मिलकर हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ CAQM और दिल्ली सरकार की शिकायत की जायेगी. क्योंकि ये टैक्सी बसें हमारी रोजी रोटी का साधन है

और इस से हमारा परिवार निर्भर है. इन टैक्सी बसों की अभी किस्तें जाती है क्योंकि कुछ टैक्सी बसें सन 2019 के आस पास ही खरीदी गई है और वैसे ही करोना महामारी में 2 साल गाड़ियाँ पार्किंग में ही ख़डी रही है.

ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का सरोपा देकर स्वागत किया और आने वाले समय में बड़े आंदोलन की तैयारी की शरुआत भी कर दी, क्योंकि अगर BS 4 डीजल टैक्सी बसें दिल्ली एनसीआर में बंद की जाती है तो इसका असर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से आने वाली लाखों डीजल BS 4 की टैक्सी बसों पर पड़ेगा और वो एनसीआर के बॉर्डर पर ही रूक जाएंगी.

दिल्ली पुलिस के सर्वे में बड़ा खुलासा: राजधानी की इन सड़कों और फ्लाईओवर पर लगता है सबसे ज्यादा जाम, ये है वजह

परिवहन विशेष न्यूज

राष्ट्रीय राजधानी गत कई वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में यातायात जाम और प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। सड़कों पर लगने वाले जाम की सबसे बड़ी वजह वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने के साथ ही कई अन्य कारण हैं। जाम के कारण समय खराब होने के साथ प्रदूषण को भी अधिक बढ़ावा मिलता है। यातायात पुलिस ने जाम और प्रदूषण को लेकर एक सर्वे कराया है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी गत कई वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में यातायात जाम और प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। सड़कों पर लगने वाले जाम की सबसे बड़ी वजह वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने के साथ ही कई अन्य कारण हैं।

जाम लगने के कारण समय खराब होने के साथ ही प्रदूषण को भी अधिक बढ़ावा मिलता है। दिल्ली यातायात पुलिस ने जाम और इससे होने वाले प्रदूषण को लेकर एक सर्वे कराया है। जिसमें अक्सर जाम लगने वाली कुल 117 सड़कें और 10 फ्लाईओवर की पहचान की गई।

इस सर्वे में पाया गया है कि फर्राटा भरते वाहन सड़कों की क्षमता से कहीं अधिक हैं। एक सड़क लंबी दूरी तक एक समान चौड़ाई में नहीं हैं, वह कहीं पर प्रर्याप्त चौड़ाई में हैं तो कहीं पर बोटल नेक या फिर कम चौड़ाई की स्थिति में हैं। ऐसे में वाहनों की अधिक संख्या के कारण जाम की स्थिति बन रही है। यातायात पुलिस के विशेष आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव की देखरेख में बनी टीम द्वारा जाम के कारणों की पहचान करने के लिए विस्तृत रिपार्ट तैयार की है। इस सर्वे का प्रमुख उद्देश्य उन कारकों की पहचान करना और समझना है, जिसके चलते चिन्हित जगहों पर जाम की समस्या उत्पन्न होती है, ताकि सड़क निर्माण से जुड़ी एजेंसियों व अन्य विभागों के अधिकारियों से तालमेल कर कमियों को दूर किया जा सके। सर्वे रिपोर्ट में यातायात पुलिस ने जाम के कारणों में सबसे प्रमुख वाहनों का अत्याधिक दबाव, सड़क किनारे और सड़क पर निर्माण कार्य और सड़क पर अतिक्रमण बताया है।

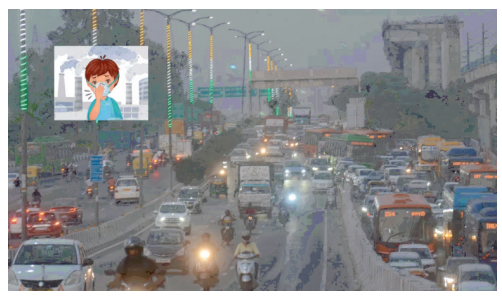

यह सड़कें जहां सबसे ज्यादा लगरहा जाम.....

निर्माण विहार-विकास मार्ग,
आईएसबीटी आनंद विहार रोड नंबर 56,
साईं चौक-नरवाना रोड,
मौजपुर, सोनिया विहार पुस्ता रोड,
दुर्गा पुरी चौक, जीटीबी क्रॉसिंग, ताहिर पुर,
किंग्सवे कैंप, हकीकत नगर,
रोड नंबर 42 (मधुबन से एमजीएम रिंग रोड),
एच ब्लाइंट आजादपुर से राणा प्रताप बाग,
मधुबन चौक से पावर हाउस,
रोहिणी-पश्चिम मेट्रो स्टेशन,
साईं बाबा चौक, अवंतिका चौक,
रिठाला मेट्रो स्टेशन, डीसी चौक,
करारी फाटक, घेवरा फाटक,
संजय गांधी टीपीटी नगर से मेट्रो स्टेशन समयपुर बादली, लिबासपुर अंडरपास लोअर जीटीके रोड,
गुज्जर चौक भलस्वा डेयरी,
महादेव चौक से शाहबाद डेयरी बवाना रोड,
स्वामी स्वरूपानंद मार्ग रामदेव चौक से वाई-प्वाइंट नरेला तक, बवाना चौक से कंझावला मोड़,
नेताजी सुभाष मार्ग (दिल्ली गेट से नुक्कड़ फैज बाजार), नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अजमेरी गेट चौक,
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार,
पहाड़गंज की ओर, रानी झांसी रोड, आनंद पर्वत, बाहरी रिंग रोड, मजनू का टीला, बुलेवार्ड रोड, तीस हजारी कोर्ट के सामने, यूसुफ सराय मार्केट, अंधरिया मोड़ (एमजी रोड), सीडीआर चौक (एमजी रोड), वाई प्वाइंट (एसएसएन मार्ग), जे.बी. टीटो मार्ग-एलबीएस मार्ग पर चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के नीचे,
शेख सराय-एलबीएस मार्ग टी-प्वाइंट,
खानपुर टी-प्वाइंट एम.बी. रोड,
सावित्री फ्लाईओवर-आउटर रिंग रोड,
हमदर्द टी-प्वाइंट एम.बी. रोड,
तारा अपार्टमेंट-अलकनंदा रोड साकेत मेट्रो,
खानपुर टी-प्वाइंट एम.बी. रोड,
हमदर्द टी-प्वाइंट एम.बी. रोड बीपी मार्ग, पारस चौक, मदनपुर खादर-मथुरा रोड, क्राउन पलाजा-मां आनंदमयी मार्ग जामिया नगर, भिंडर प्वाइंट, सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, पुराना किला रोड, किर्बी प्लेस, रंगपुरी अंडर फ्लाईओवर एनएच-48, सफदरजंग अस्पताल के सामने, नांगलोई चौक (रोहतक रोड), करमुद्दीन रेड लाइट से मुंडका इंडस्ट्रीज मेट्रो स्टेशन तक, रोहतक रोड, खंडा चौक (नीलोठी-मीरा बाग रोड), मंगोलपुरी फ्लाईओवर के नीचे, आउटर रिंग रोड, भेरा एन्क्लेव गोल चक्कर पर बाहरी रिंग रोड, मंगोलपुरी फ्लाई ओवर के नीचे पीरा गढ़ी चौक, बाहरी रिंग रोड, फिरनी रोड-नजफगढ़, नजफगढ़ से नागलोई रोड, छावला ड्रेन, रोड नंबर 201 सेक्टर-1 द्वारका, राजा पुरी रोड नंबर 201 (मधुविहार से सेक्टर 3/13 क्रासिंग), नजफगढ़ रोड पर द्वारका मोड़-ओल्ड पालम कट, पंजाबी बाग, राजा गार्डन फ्लाइओवर (इनर रिंग रोड) दोनों कैरिजवे, पंजाबी बाग आर/ए से राजा गार्डन फ्लाईओवर (इनर रिंग रोड) दोनों कैरिजवे, डिस्ट्रिक्ट सेंटर से उत्तम नगर चौक आदि सड़कें।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

मिसाल बेमिसाल

डॉ. किरण बेदी

देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर

डॉ॰ किरण बेदी (जन्म : ९ जून १९४९) भारतीय पुलिस सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी एवं राजनेता हैं। वर्तमान में वह पुदुचेरी की उपराज्यपाल हैं। सन १९७२ में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली वे प्रथम महिला अधिकारी हैं। 35 वर्ष तक सेवा में रहने के बाद सन 2007 में उन्होने स्वैच्छिक सेवानिवृति ले ली। उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वे संयुक्त आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण तथा दिल्ली पुलिस स्पेशल आयुक्त (खुफिया) के पद पर कार्य कर चुकी हैं।

एक किशोरी के रूप में, बेदी 1966 में राष्ट्रीय जूनियर टेनिस चैंपियन बनीं। 1965 और 1978 के बीच, उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में कई खिताब जीते। IPS में शामिल होने के बाद, बेदी ने दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ और मिजोरम में सेवा की। उन्होंने दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में एक सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के रूप में अपना करियर शुरू किया, और 1979 में राष्ट्रपति का पुलिस पदक जीता। इसके बाद, वह पश्चिम दिल्ली चली गईं, जहां उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी लाई। इसके बाद, एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के रूप में, वह दिल्ली में 1982 के एशियाई खेलों के लिए यातायात व्यवस्था की देखरेख करती हैं और 1983 की CHOGM गोवा में मिलती हैं। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी के रूप में, उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक अभियान चलाया, जो नवज्योति दिल्ली पुलिस फाउंडेशन (2007 में नवज्योति इंडिया फाउंडेशन का नाम बदलकर) में विकसित हुआ।

मई 1993 में, वह दिल्ली जेल में महानिरीक्षक (IG) के रूप में तैनात हुईं। उन्होंने तिहाड़ जेल में कई सुधारों की शुरुआत की, जिसे दुनिया भर में प्रशंसा मिली और 1994 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। 2003 में, बेदी पहली भारतीय महिला बनीं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में महासचिव के पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। शांति संचालन के संचालन। सामाजिक सक्रियता और लेखन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसने 2007 में इस्तीफा दे दिया। उसने कई किताबें लिखी हैं, और इंडिया विजन फाउंडेशन चलाती है। 2008-11 के दौरान, उन्होंने एक कोर्टशो आप की कचहरी भी होस्ट की। वह 2011 के भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थीं, और जनवरी 2015 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। उन्होंने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सफल रूप से चुनाव लड़ा। 22 मई 2016 को , बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था।

१९७०-७२ में किरण बेदी ने अपने अकादमिक करियर की शुरुआत खालसा महिला कॉलेज, अमृतसर में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता के तौर पर की। जुलाई, १९७२ में वह भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हो गईं और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।

सम्मान एवं पुरस्कार

उनके मानवीय एवं निडर दृष्टिकोण ने पुलिस कार्यप्रणाली एवं जेल सुधारों के लिए अनेक आधुनिक आयाम जुटाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। निःस्वार्थ कर्त्तव्यपरायणता के लिए उन्हें शौर्यपुरस्कार मिलने के अलावा अनेक कार्यों को सारी दुनिया में मान्यता मिली है जिसके परिणामस्वरूप एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाने वाला रमन मैगसेसे पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। उनको मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रृंखला में शामिल हैं - जर्मन फाउंड्रेशन का जोसफ ब्यूज पुरस्कार, नार्वे के संगठन इंटरशनेशनल ऑर्गेनाजेशन ऑफ गुड टेम्पलर्स का ड्रग।

विवाद

जुलाई 1994, किरण बेदी, तिहाड़ जेल के कारागार महानिरीक्षक फिर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की शुरुआत से एक विचाराधीन कैदी विदेशी चिकित्सा ध्यान प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करने के लिए निकाला गया था। 1988 में वाधवा आयोग बेदी के कार्यालय के बाहर एक सहयोगी के गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध वकीलों पर उसे लाठी - प्रभार में भूमिका के लिए बेदी की आलोचना की। करन थापर, कई लोकप्रिय साक्षात्कार के मेजबान से पता चलता है बेदी आसपास के विवादों पर एक लेख प्रकाशित के बाद वह एक के बाहर खींच लिया थापर के साक्षात्कार शो।

बेदी लोकपाल विधेयक पर सरकार के साथ वार्ता में एक कट्टरपंथी होने के लिए आलोचना की थी। बाद में संसद के सदस्यों के लिए लोकपाल विधेयक के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर सांसदों को मजाक के लिए किरण बेदी और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लंघन लाने का प्रस्ताव है, हालांकि नोटिस बाद में वापस ले लिया।

किरण बेदी के आरोप लगाया गया था उसे भुगतान रियायती किराया के बावजूद उसे हवाई टिकट के लिए पूरा किराया मेजबान का आरोप लगाया है। वह भी उसे मेजबान व्यापार वर्ग किराया का आरोप लगाया है, जबकि अर्थव्यवस्था वर्ग उड़ान और झूठे चालान पेश आरोप लगाया गया था। बेदी का दावा व्यापार वर्ग दिल्ली से मुंबई किराया के एक गैर सरकारी संगठन ने आरोप लगाया था, जबकि उसे यात्रा intineray उन्हें संप्रेषित से पता चला है कि वह पास के पुणे से उड़ रहा था। किरण बेदी ने कहा है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए पैसे अर्जित नहीं किया गया था, लेकिन उसे गैर - सरकारी संगठन को दिया गया।

1992 में किरण बेदी की बेटी दिल्ली हार्डिंग कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए छात्र उत्तर - पूर्व से के लिए एक कोटा के तहत प्रवेश दिया गया था। किरण बेदी को मिजोरम में उस समय तैनात किया गया था। वह उसकी बेटी कह रही है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को ऐसी योजनाओं के हकदार हैं एक आरक्षित सीट में भर्ती कराया कदम का बचाव किया था।

26 नवम्बर 2011, दिल्ली स्थित एक वकील देविंदर सिंह चौहान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अमित बंसल ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के भीतर किरण बेदी के खिलाफ एक मामला दर्ज करने के लिए, कथित तौर पर धन के बेजा इस्तेमाल के लिए उसे गैर सरकारी संगठनों के लिए नतीजतन, दिल्ली पुलिस बेदी के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (अमानत में खयानत), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) आईपीसी के तहत एक मामला दर्ज किया है।

सामाजिक पहल

किरण बेदी 17 अन्य पुलिस अधिकारियों को 1987 में नवज्योति इंडिया फाउंडेशन (एनआईएफ) की स्थापना के साथ, एनआईएफ ड्रग नशा के लिए एक नशा मुक्ति और पुनर्वास की पहल के साथ शुरू कर दिया है और अब संगठन निरक्षरता और महिलाओं की तरह अन्य सामाजिक मुद्दे के लिए विस्तार किया गया है सशक्तिकरण 1994 बेदी सेटअप इंडिया विजन फाउंडेशन जो पुलिस सुधारों, जेल सुधारों के क्षेत्र में काम करता है, महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण और सामुदायिक विकास उनके प्रयासों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान जीत लिया है और उसके संगठनों से सम्मानित किया गया ₹नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सर्ज Soitiroff संयुक्त राष्ट्र द्वारा मेमोरियल पुरस्कार ₹।

लोकपाल आंदोलन

किरण बेदी 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ी, अरविंद केजरीवाल के अलावा किरण बेदी भी इंडिया अगेन्स्ट करप्शन (I.A.C) के प्रमुख सदस्यों में से एक रही हैं। (I.A.C) ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध किया और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार से एक मजबूत लोकपाल विधेयक लाने का आग्रह किया। सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच कई विचार विमर्श के बारह दिनों के बाद, संसद में लोकपाल का मसौदा तैयार करने में तीन बिंदुओं पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।

फिल्मों और साहित्य में

किरण बेदी के जीवन पर एक गैर कथा फीचर फिल्म, हाँ मैडम, सर, ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता, Megan Doneman द्वारा उत्पादन किया गया है। इस फिल्म को दुनिया भर के फिल्म समारोहों में दिखाई है। इसका टीकाकार एक अकादमी पुरस्कार विजेता, हेलेन मिरेन है। किरण बेदी टोरंटो, दुबई और एडिलेड में अपने प्रदर्शन के दौरान मौजूद थे और प्रत्येक शो के अंत में क्यू और एक सत्र को संबोधित करने के लिए। वृत्तचित्र पुरस्कार श्रेणियों की एक क्लीन स्वीप --- 100,000 डॉलर का एक नकद पुरस्कार के साथ ₹सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र₹ अमेरिका में किसी भी फिल्म महोत्सव और सांता बारबरा अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म में 2500 डॉलर के साथ सामाजिक न्याय पुरस्कार में एक वृत्तचित्र के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया है महोत्सव. हां मैडम, सर जूरी से एक सर्वसम्मत वोट मिला है। 2006 में, नार्वेजियन mPower फिल्म और मीडिया और फिल्म निर्माता Rakkenes Øystein गांधी के नक्शेकदम में बेदी और उसे तिहाड़ केंद्रीय कारागार में जेल क्रांति पर एक और वृत्तचित्र, जारी किया। फिल्म अटलांटा में भारत - अमेरिकी फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र नवंबर 2006 में सम्मानित किया गया। किरण बेदी ने भी 2009-10 में टीवी शो आप की Kachehri स्टार प्लस पर किरण के साथ मेजबान बन गया।

अन्य उपलब्धियाँ

व्यावसायिक योगदान के अलावा उनके द्वारा दो स्वयं सेवी संस्थाओं की स्थापना तथा पर्यवेक्षण किया जा रहा है। ये संस्स्थाएं हैं- 1988 में स्थापित नव ज्योति एवं 1994 में स्थापित इंडिया विजन फाउंडेशन। ये संस्थाएं रोजना हजारों गरीब बेसहारा बच्चों तक पहुँचकर उन्हें प्राथमिक शिक्षा तथा स्त्रियों को प्रौढ़ शिक्षा उपलब्ध कराती है। 'नव ज्योति संस्था' नशामुक्ति के लिए इलाज करने के साथ-साथ झुग्गी बस्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों में तथा जेल के अंदर महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श भी उपलब्ध कराती है। डॉ॰ बेदी तथा उनकी संस्थाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान तथा स्वीकार्यता प्राप्त है। नशे की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया 'सर्ज साटिरोफ मेमोरियल अवार्ड' इसका ताजा प्रमाण है।

वे एशियाई टेनिस चैंपियन रही हैं। उन्होंने कानून की डिग्री के साथ-साथ 'ड्रग एब्यूज एण्ड डोमोस्टिक वायलेंस' विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है। उन्होंने 'इट्स ऑलवेज पॉसिबल' तथा दो आत्मकथा 'आय डेयर' एवं 'काइंडली बेटन' नामक पुस्तक लिखी है। इसके अलावा यथार्थ जीवन पर आधारित वृतांतों का संकलन 'व्हाट वेंट रोंग' नाम से किया है। इसके हिन्दी रुपांतर 'गलती किसकी' नाम से संकलित है। ये दोनों संकलन, दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' एवं 'नवभारत टाइम्स' में डॉ॰ बेदी के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित पाक्षिक स्तभों से संबंधित हैं।

प्रमुख पद

दिल्ली यातायात पुलिस प्रमुख
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरो
डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, मिजोरम
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिज़न, तिहाड़
स्पेशल सेक्रेटरी टू लेफ्टीलेन्ट गवरनर, दिल्ली
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, चंडीगढ़
जाइंट कमिश्नर ऑफ पुलीस ट्रेनीग
स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलीस इंटेलिजेन्स
यू.एन. सिविलियन पुलीस एड्वाइजर
महानिदेशक, होम गार्ड और नागरिक रक्षा
महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

समता, ममता और महिलाएं

देश में महिला अधिकारों के पक्षकार संगठनों की कमी नहीं है, पर हाल ही में मुझे एक और ऐसे संघ की सदस्याओं से मिलने का मौका मिला जिसने मुझे महिलाओं की एक और समस्या पर फिर से सोचने के लिए विवश किया। देश की राजधानी दिल्ली के लिए यह कोई नई बात नहीं है कि किसी संगठन के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए आएं या मीडियाकर्मियों से मिलकर अपनी समस्याओं का बखान करें। महिलाओं के इस संगठन की प्रकृति और इसके उद्देश्य ने सचमुच मेरी आंखें खोली हैं। राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच नामक इस संगठन की सदस्या महिलाओं में विधवाएं, परित्यक्ताएं, तलाकशुदा महिलाएं व ऐसी अविवाहित महिलाएं शामिल हैं जो अपने परिवार और समाज से उपेक्षापूर्ण व्यवहार का दंश झेल रही हैं। इनमें से अधिकांश ग्रामीण पृष्ठभूमि की साधनहीन महिलाएं हैं जिनके पास अपनी कठिनाइयां बताने का कोई उपाय नहीं था। यह संगठन ऐसी महिलाओं के अधिकारों की वकालत ही नहीं करता बल्कि उन्हें अधिकारों के प्रति शिक्षित भी करता है। इससे भी बड़ी बात, यह सिर्फ ऐसी वंचिता महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने के साथ-साथ उनके ससुराल पक्ष के परिवारों को काउंसलिंग के माध्यम से उनके बीच की गलतफहमियां दूर करके परिवारों को जोडने का प्रयत्न भी करता है। यानी राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच अधिकारों की वकालत करते हुए सिर्फ झगड़ा बढ़ाने का ही काम नहीं करता, बल्कि झगड़ा निपटाने का रचनात्मक प्रयत्न भी करता है।

अपने ममतामयी दृष्टिकोण के लिए जानी जाने वाली महिलाएं विपरीत स्थितियों में खुद कितनी उपेक्षा का शिकार होती हैं, इसकी कहानी सचमुच अजीब है। पुरुष प्रधान समाज में अकेली महिलाओं की स्थिति अक्सर शोचनीय होती है और उन पर कई और नए बंधन लाद दिए जाते हैं। विधवा महिलाएं ससुराल में शेष सदस्यों के अधीन हो जाती हैं, परित्यक्ताएं और तलाकशुदा महिलाएं तो कई बार अपने मायके में भी दूसरे दर्जे की नागरिक बनकर रह जाती हैं। घर में सारा दिन काम करते रहने पर भी उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता, स्वतंत्रता नहीं मिलती और अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता। विधवाओं की कठिनाइयों के बारे में तो फिर गाहे-बगाहे बात होती रहती है, लेकिन परित्यक्ताओं, तलाकशुदा एकल महिलाओं, किसी भी विवशतावश अथवा अपनी इच्छा से अविवाहित रह गई महिलाओं की समस्याओं के बारे में हम शायद ज्यादा जागरूक नहीं हैं। एकल महिलाओं को हिंसा, शोषण, उपेक्षा, तिरस्कार, अवैतनिक कामकाज के अलावा यौन शोषण की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांवों में उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होता, समाज की रूढ़िवादिता और संस्कार उन्हें विरोध करने से रोकते हैं और वे असहाय पिसती रह जाती हैं। सन-2011 की जनगणना के अनुसार ऐसी महिलाओं की संख्या पांच करोड़ साठ लाख के आसपास थी और इनमें से अधिकांश विधवाएं थीं। खेद का विषय है कि ऐसी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही नहीं, जिन परिवारों में मर्द लोग कामकाज के सिलसिले में शहर से बाहर रहने को विवश हैं, वहां उनकी पत्नियां घर में अकेली पड़ जाती हैं और कई तरह की समस्याएं झेलती हैं, लेकिन जुबान नहीं खोल पातीं।

घर से बाहर रह रहा मर्द अगर कठिनाइयां झेल कर पैसे कमाता है तो घर में अकेली पड़ गई उसकी पत्नी भी कई तरह से अपमान और उपेक्षा का शिकार हो रही हो सकती है। महिलाओं की शारीरिक बनावट के कारण उनकी समस्याएं अलग हैं। यही नहीं, उनकी भावनात्मक सोच भी पुरुषों से अलग होती है और अक्सर पुरुष उसे नहीं समझ पाते। इसके कारण भी कई बार महिलाओं को कई तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। भौगोलिक दूरी के कारण अलग-अलग स्थानों पर रह रहे पति-पत्नी में पत्नी इसलिए मुरझा जाती है कि वह पति के संसर्ग और सहारे, दोनों से वंचित रह जाती है और कुछ बोल भी नहीं पाती। इससे भी ज्यादा बड़ी समस्या तब आती है जब रोजगार के सिलसिले में मर्द शहर से बाहर जाता है और वहीं पर दूसरा विवाह कर लेता है। ऐसे बहुत से पुरुष अपनी पहली पत्नी को अक्सर पूरी तरह से बिसरा देते हैं या फिर दोनों महिलाओं से झूठ बोलते रह सकते हैं। राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच की सदस्याएं महिलाओं की इस व्यथा का बखान करते हुए कहती हैं कि आईटी सेक्टर के विकास के कारण एक नई समस्या बनी है। हिमाचल प्रदेश में इस सेक्टर में रोजगार की बहुलता न होने के कारण मर्दों का राज्य से बाहर प्रवास जितना आम है, नए शहर में बस कर आधुनिक महिलाओं अथवा महिला सहकर्मियों से दूसरी शादी भी कम आम नहीं है। हिमाचल प्रदेश जैसे कम आबादी वाले छोटे से राज्य से ही राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच की सदस्याओं की संख्या हजारों में है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं शोषण और उपेक्षा का शिकार हो रही हैं। महिलाओं की एक अन्य समस्या को भी पुरुष अक्सर नहीं समझ पाते और अक्सर उसका परिणाम यह होता है कि पूरा परिवार बिखर जाता है।

करियर के जाल में फंसा पुरुष वर्ग पत्नी और परिवार की उपेक्षा की गंभीरता को समझ ही नहीं पाता, कई बार तो तब तक जब परिवार टूट ही न जाए या टूटने के कगार पर ही न पहुंच जाए। तब भी पुरुष लोग यह नहीं समझ पाते कि वे कहां गलत थे। वे तो तब भी यही मान रहे होते हैं कि वे जो कुछ भी कर रहे थे वह परिवार की भलाई, खुशी और समृद्धि के ही लिए था। यहां पतियों और पत्नियों का नजरिया एकदम अलग-अलग नजर आता है। पत्नियां पैसा कम और पति का साथ ज्यादा चाहती हैं और पति यह मानते रह जाते हैं कि यदि उनके पास धन होगा तो वे पत्नी के लिए सारे सुख खरीद सकेंगे, बिना यह समझे कि उनकी पत्नी की भावनात्मक आवश्यकताएं भी हैं और उनकी पूर्ति के लिए उन्हें पति के पैसे की नहीं, बल्कि पति के संसर्ग और भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता है। हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है, हमारे जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, लेकिन सोच बदलने में समय लग रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में अभी भी रूढ़िवादिता का बोलबाला है। अब समय आ गया है कि हम पुरुष समाज को महिलाओं की आवश्यकताओं के बारे में शिक्षित करें और महिलाओं के प्रति ज्यादा सौहार्दपूर्ण रवैया अपनाएं ताकि समाज के दोनों अंगों का समान विकास संभव हो सके और समाज में संतुलन बना रहे।

पत्नियां पैसा कम और पति का साथ ज्यादा चाहती हैं और पति यह मानते रह जाते हैं कि यदि उनके पास धन होगा तो वे पत्नी के लिए सारे सुख खरीद सकेंगे, बिना यह समझे कि उनकी पत्नी की भावनात्मक आवश्यकताएं भी हैं और उनकी पूर्ति के लिए उन्हें पति के पैसे की नहीं, बल्कि पति के संसर्ग और भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता है। हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है, हमारे जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, लेकिन सोच बदलने में समय लग रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में अभी भी रूढ़िवादिता का बोलबाला है। अब समय आ गया है कि हम पुरुष समाज को महिलाओं की आवश्यकताओं के बारे में शिक्षित करें और महिलाओं के प्रति ज्यादा सौहार्दपूर्ण रवैया अपनाएं ताकि समाज के दोनों अंगों का समान विकास संभव हो सके और समाज में संतुलन बना रहे

जहरीली हुई दिल्ली की हवा, सांसों का संकट शुरू; ग्रेप का पहला चरण लागू

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता पहुंचते ही दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप का पहला चरण लागू कर दिया गया है। अब डीजी सेट व पटाखों पर रोक सहि 27 सूत्री एक्शन प्लान लागू हो गया है। बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली में शराब श्रेणी की हवा गुणवत्ता दर्ज की गई। वहीं गुरुवार को शाम के समय मध्यम श्रेणी की हवा रही थी।

नई दिल्ली। दिल्ली में हवा (Delhi Air Quality) 'खराब' श्रेणी में पहुंच गई। खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता पहुंचते ही दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप का पहला (Grap-1) चरण लागू कर दिया गया है। अब डीजी सेट व पटाखों पर रोक सहि 27 सूत्री एक्शन प्लान लागू हो गया है।

खराब श्रेणी की हुई हवा की गुणवत्ता

शुक्रवार को दिल्ली में शराब श्रेणी की हवा गुणवत्ता दर्ज की गई। वहीं, गुरुवार को राजधानी के आठ इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 ऊपर यानी 'खराब' श्रेणी में पहुंच गया। यह बात अलग है कि समग्रतौर पर अभी वायु गुणवत्ता "मध्यम" श्रेणी में बनी हुई है।

दिल्ली-NCR में ग्रेप-1 लागू

एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंचते ही सीएक्यूएम की ग्रेप उप समिति की आपात बैठक में दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप का पहला चरण लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान खुले में कूड़ा जलाने, नियमित बिजली आपूर्ति के लिए डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल व पटाखों पर रोक सहित 27 सूत्री एक्शन प्लान को किया लागू कर दिया गया है।

अगस्त-सितंबर में हुई कम बारिश

खास बात है कि इस बार अगस्त और सितंबर में एनसीआर में सामान्य से कम बरसात हुई। इसके चलते यहां पर जमीन में नमी की मात्रा कम है और हवा के साथ धूल ज्यादा उड़ रही है। इसके अलावा मानसून की वापसी के बाद हवा की दिशा भी उत्तरी-पश्चिमी हो गई है। इसकी रफ्तार भी कम है। इसीलिए धूल कणों से होने वाला प्रदूषण (Delhi Air Pollution) ज्यादा देर तक वातावरण में ठहर रहा है।

तीस हजारी कोर्ट फायरिंग मामले में अदालत में हुई सुनवाई, आठ वकीलों को मिली जमानत

तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों के बीच झड़प के दौरान हुई फायरिंग की घटना में गिरफ्तार आठ आरोपित वकीलों को अदालत ने जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन सिंह राजावत ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और इसमें काफी समय लगेगा।

नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों के बीच झड़प के दौरान हुई फायरिंग की घटना में गिरफ्तार आठ आरोपित वकीलों को अदालत ने जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन सिंह राजावत ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और इसमें काफी समय लगेगा।

इस शर्त पर दी जमानत

अदालत ने कहा कि आरोपित करीब 90 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं और मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। अदालत ने आठों आरोपित राम पांडे, ललित शर्मा, मनीष शर्मा, सचिन सांगवान, राहुल शर्मा, रवि गुप्ता, अमन सिंह और जितेश खारी को 50 हजार के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने की शर्त पर जमानत दे दी।

पांच जुलाई को घटी थी घटना

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पांच जुलाई को वकीलों के दो समूहों के बीच झड़प के दौरान अदालत परिसर में गोलियां चलाई गई। उन्होंने बताया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चतिंदर सिंह ने दिल्ली पुलिस की ओर से तीन सितंबर को दायर आरोपपत्र के मामले का संज्ञान लेने के बाद मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर के लिए तय कर दी। पूरा मामला आठ आरोपितों और कुछ अन्य के खिलाफ शस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी से उपजा है।

डीडीए जल्द खोलेगा रोशनआरा क्लब के क्रिकेट ग्राउंड और बाहरी क्षेत्र, जानिए क्या है पूरा प्लान

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि अगले सप्ताह से क्लब के बाहरी क्षेत्र को खोलने पर विचार कर रहा है। डीडीए ने पीठ के समक्ष यह जानकारी रोशनआरा क्लब द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। डीडीए एक सप्ताह के भीतर बीसीसीआई मैदान क्रिकेट मैदान और अन्य मैदानों सहित बाहरी सुविधाओं को खोलने पर विचार कर रहा है।

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि अगले सप्ताह से क्लब के बाहरी क्षेत्र को खोलने पर विचार कर रहा है। क्लब को हाल ही में डीडीए ने सील कर दिया था। डीडीए ने न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ के समक्ष कहा कि क्लब वही रहेगा, सिर्फ इसका स्वामित्व केवल भूमि मालिक एजेंसी के पास होगा।

डीडीए ने पीठ के समक्ष यह जानकारी रोशनआरा क्लब द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। वहीं, रोशनआरा क्लब की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी और मोहित माथुर ने कहा कि अप्रैल माह में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निर्देश दिया था कि क्लब के खिलाफ केवल इस आधार पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा कि याचिकाकर्ता क्लब का पट्टा समाप्त हो गया है।

उन्होंने कहा कि क्लब से जुड़ा एक मामला उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष भी लंबित है। उन्होंने तर्क दिया कि बेदखली लागू कर दी गई है जबकि पट्टे के नवीनीकरण का सवाल अभी भी लंबित है। वहीं, डीडीए की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने कहा कि क्लब के सदस्य सदस्य बने रहेंगे और डीडीए को संपत्ति पर अपने स्वामित्व का प्रयोग करने का अधिकार है।

इस पर पीठ ने कहा कि यह एक क्लब नहीं रहेगा। एएसजी ने जवाब दिया कि यह क्लब बना रहेगा और इसका स्वामित्व अब डीडीए के पास वापस आ गया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से पट्टा डीडीए के पास वापस आ गया है और वे सभी के लिए पोर्टल खोलेंगे।

उन्होंने दलील दी कि इस मामले में अवमानना का मामला नहीं बनता है और यह अवमानना याचिका डीडीए को दबाने के लिए दायर की गई है। डीडीए की स्थायी अधिवक्ता मनिका त्रिपाठी ने कहा कि डीडीए एक सप्ताह के भीतर बीसीसीआई मैदान, क्रिकेट मैदान और अन्य मैदानों सहित बाहरी सुविधाओं को खोलने पर विचार कर रहा है।

यह भी कहा कि अब रोशनआरा क्लब का प्रबंधन डीडीए का रहेगा क्योंकि स्वामित्व डीडीए का है। इसलिए हम बगीचों और अन्य चीजों की देखभाल करेंगे। इस पर पीठ ने कहा कि अगर यही कार्ययोजना है तो पूरा संदर्भ और पृष्ठभूमि बदल जाएगी।

अदालत ने कहा कि अगर डीडीए हर 60 या 99 साल के बाद पट्टे समाप्त करने जा रहे हैं तो निरंतरता या विरासत कहां है? फिर कोई विरासत नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई को स्थगित करते हुए डीडीए अधिवक्ता को

'खुद काम नहीं करेंगे और किसी को भी नहीं करने देंगे' संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे हैं जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि मोदी सरकार न खुद कुछ करती है न दूसरों को करने देती है। मीडिया बातचीत के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस हमारा समर्थन न करें क्या फर्क पड़ता है।

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि मोदी सरकार न खुद कुछ करती है, न दूसरों को करने देती है। साथ ही उन्होंने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के सशर्त समर्थन करने पर भी हमला बोला है।

AAP नेताओं पर घोटालों की जांच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला किया। सीएम केजरीवाल ने कहा,₹हमें इतनी जांच की, कुछ नही निकला। कल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पूरे शराब स्कैम को झूठा बताया, कोई भी पैसा नहीं बदला गया। कुछ दिनों में, शराब स्कैम बंद हो जाएगा और वे कुछ और नया लेकर सामने आएंगे। उन्हें बस लोगों को एजेंसियों और जाँचों में उलझाएं रखना है। खुद काम नहीं करेंगे और किसी को भी काम करने नहीं देंगे₹

फर्जी है पूरा शराब घोटाला

समाचार एजेंसी के मुताबिक, लैंडफिल साइट का दौरा करने के बाद मीडिया बातचीत के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस हमारा समर्थन न करें, क्या फर्क पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, लेकिन कुछ नहीं निकला...आपने कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को सुना, पूरा शराब घोटाला झूठा है, एक पैसे का भी लेन-देन नहीं हुआ। जज सबूत मांगते रहे, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। कुछ ही दिनों में शराब घोटाला... को बंद कर देंगे, कोई और घोटाला ले आएंगे।

दिल्ली में साथ, पर पंजाब में मतभेद

आपको बता दें कि शुक्रवार को कांग्रेसी सांसद केसी वेणुगोपाल ने आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध करने के साथ ही पंजाब में सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी का भी विरोध किया है। पंजाब पुलिस ने सुखपाल को 2015 के ड्रग्स तस्करी मामले में 28 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जहां से अदालत ने खैरा को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

स्टैंडिंग कमेटी के गठन के बाद नई कंपनियों को मिलेगी जिम्मेदारी

वहीं, उन्होंने लैंडफिल साइट पर कूड़ा निस्तारण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़ा निस्तारण का काम काफी धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि यहां तीन कंपनियां काम कर रही है। जिनमें आपस में झगड़ा चल रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी बनने के बाद दो नई एजेंसियों को कूड़ा निस्तारण की जिम्मेदारी दी जाएगी।

सोने के भाव हुए कम, लोगों के खिले चेहरे; तो बाजार ने काटी चांदी

वैश्विक कारणों से ही सही दिल्ली के ज्वेलरी मार्केट में सोने के भाव में भारी गिरावट है। 10 दिन में ही इसके दाम में करीब तीन हजार रुपये प्रति 10 ग्राम में कमी देखी जा रही है। इससे ज्वेलर्स इस धनतेरस और दीपावली में 30 प्रतिशत से अधिक बिक्री की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनके मुताबिक दाम में कमी का सकारात्मक असर देखा जा रहा है।

नई दिल्ली। वैश्विक कारणों से ही सही दिल्ली के ज्वेलरी मार्केट में सोने के भाव में भारी गिरावट है। 10 दिन में ही इसके दाम में करीब तीन हजार रुपये प्रति 10 ग्राम में कमी देखी जा रही है। इससे ज्वेलर्स इस धनतेरस और दीपावली में 30 प्रतिशत से अधिक बिक्री की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

और हो सकती है गिरावट

उनके मुताबिक दाम में कमी का सकारात्मक असर देखा जा रहा है, लोग निवेश के लिहाज से सोना खरीद रहे हैं। बुधवार को दिल्ली के ज्वेलरी बाजारों में प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 58 हजार 335 रुपये में बिका। जबकि 25 सितंबर को यह 60 हजार के पार पहुंच गया था। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में और गिरावट की उम्मीद है।

7 प्रतिशत तक पहुंच सकती हैं ब्याज दरें

ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के अध्यक्ष पंकज अरोरा ने बताया कि अमेरिकी फेडरल बैंक ने अपनी ब्याज दरों में 4.6 प्रतिशत से 5.1 प्रतिशत तक की वृद्धि करने का निर्णय लिया है और संकेत दिया है कि ब्याज दरें और भी लंबे समय तक इसी तरह बनी रह सकती हैं, जबकि वित्तीय कंपनी जेपी मार्गन ने व्यापारिकों और निवेशकों को चेताया है कि ब्याज दरें 7 प्रतिशत तक पहुंच सकती हैं। सोने के दामों में गिरावट के पीछे चीन के कई

रियल एस्टेट कंपनियों के दिवालिया होने को भी कारण के रूप में गिनाया जा रहा है।

पंकज अरोरा ने बताया कि दिवालिया होने पर पहुंच रही चीन की इन रियल एस्टेट कंपनियों में हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियां अपनी हिस्सेदारी बेच रही हैं। द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, कूचा महाजनी के चेयरमैन योगेश सिंघल कहते हैं कि रूस व यूक्रेन युद्ध से जो वैश्विक युद्ध का भय था, वह अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। इसलिए निवेशकों में आर्थिक अस्थिरता के अनुमान पर सोने में निवेश का रूझान कम हुआ है। इस कारण भी वैश्विक स्तर पर सोने के दाम में गिरावट जारी रह सकती है।

"एडिटर और उनके साथी द्वारा गैर कानूनी रूप से धन का गबन किया गया"

देश की संप्रभुता को चोट पहुंचाने के लिए चीन से लिया गया पैसा', न्यूज क्लिक के खिलाफ एफआईआर में कई गंभीर आरोप

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी एफआईआर में कहा कि ये लोग वैश्विक और घरेलू स्तर पर चीन के प्रोपेगेंडा के तहत कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र बताते हैं। FIR के मुताबिक न्यूजक्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और उनके साथी जोसेफ राज अनूप चक्रवर्ती बप्पादित्या सिन्हा द्वारा गैर कानूनी रूप से धन का गबन किया है।

नई दिल्ली। **ऑनलाइन** पोर्टल न्यूजक्लिक के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए और आईपीसी की धाराओं में, जो एफआईआर दर्ज की है उसके तथ्य अब सामने आए हैं। चीन से फंडिंग मिलने के आरोपों से घिरे न्यूजक्लिक के प्रमोटरों और उससे जुड़े पत्रकारों पर पुलिस ने गंभीर आरोप में मुकदमे दर्ज किए हैं।

पुलिस ने अपनी एफआईआर में कहा कि इन लोगों ने वैश्विक और घरेलू स्तर पर देश की संप्रभुता को चोट पहुंचाने के लिए पैसा लिया और प्रोपेगेंडा के तहत कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र बताया है।

चीन से पैसा लेकर फैलाया प्रोपेगेंडा: पुलिस

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पुलिस ने आरोप लगाया है कि ये लोग वैश्विक और घरेलू स्तर पर एक कहानी फैला रहे थे, जिसमें कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश विवादित क्षेत्र बताते रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारत की उत्तरी सीमाओं के साथ छेड़छाड़ कर कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को नक्शे में भारत के हिस्सों के रूप में नहीं दिखाने की गलत कोशिश की है जो भारत की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के इरादे से किया गया है।

पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है, भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने, भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने और एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से साजिश के तहत विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में अवैध रूप से करोड़ों की विदेशी धनराशि का निवेश किया गया है।

गैर कानूनी रूप से किया धन का गबन

FIR के मुताबिक, न्यूजक्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और उनके साथी जोसेफ राज, अनूप चक्रवर्ती (अमित चक्रवर्ती के भाई), बप्पादित्या सिन्हा (वर्चुनेट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर) द्वारा गैर कानूनी रूप से धन का गबन किया गया है।

यह भी पता चला है कि इस धन को तीस्ता सीतलवाड़ के साथी गौतम नवलखा, जावेद आनंद, तमारा, जिब्रान, उर्मिलेश, अराित्रका हलदर, परंजय गुहा ठाकुरता, त्रिना शंकर और अभिसार शर्मा के बीच बांटा गया था।

प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली HC में हुई सुनवाई, पुलिस से मांगा जवाब

चीन से फंडिंग के आरोप में जेल में बंद न्यूजक्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिसे लेकर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को लेकर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर भी दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अब कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नौ अक्टूबर को करेगी।

नई दिल्ली। चीन से फंडिंग के आरोप में जेल में बंद न्यूजक्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसे लेकर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को लेकर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर भी दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अब कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नौ अक्टूबर को करेगी।

न्यूजक्लिक पर लगे ये आरोप

बता दें कि मंगलवार के दिन पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही दिल्ली पुलिस ने न्यूजक्लिक के ऑफिस को भी सील कर दिया था। बता दें कि न्यूजक्लिक पोर्टल पर चीन समर्थक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पैसे लेने का आरोप लगा है।

कितने रिक्टर स्केल का भूकंप झेल सकती हैं नोएडा की बहुमंजिला इमारतें, दिल्ली-NCR में केंद्र रहा तो क्या होगा?

परिवहन विशेष न्यूज

अगर भूकंप का केंद्र नोएडा या दिल्ली-एनसीआर में रहता है उसकी क्षमता छह से ज्यादा होती है तो वाइब्रेशन के कारण भारी नुकसान हो सकता है। नोएडा की बहुमंजिला इमारतें सात रिक्टर स्केल तक का भूकंप झेल सकती हैं। ऐसे में शहर में जितनी भी बहुमंजिला इमारतों को तैयार किया गया है या निर्माण किया जा रहा है सभी को भूकंप रोधी बनाया जा रहा है।

नोएडा। सिसमिक जोन-4 में आने वाले नोएडा की बहुमंजिला इमारतें सात रिक्टर स्केल तक का भूकंप झेल सकती हैं। ऐसे में शहर में जितनी भी बहुमंजिला इमारतों को तैयार किया गया है या निर्माण किया जा रहा है, सभी को भूकंप रोधी बनाया जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण प्रत्येक बिल्डर से स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट लेकर ही उस परियोजना का मानचित्र स्वीकृत करता है।

नोएडा में स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लागू

निर्माण पूरा होने पर इसी रिपोर्ट के आधार पर निर्माण का निरीक्षण करने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) जारी किया जाता है। अब प्राधिकरण ने नोएडा में स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लागू कर दी है, जिसके बाद यह पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर बिल्डरों ने निर्माण कराया था या नहीं।

वास्तुविद् एवं नियोजन विभाग महाप्रबंधक इश्तियाक अहमद ने बताया कि नोएडा में जितने भी बहुमंजिला रिहायशी इमारतें बनी तो इस प्रमाण के साथ है कि वह सात रिक्टर स्केल का भूकंप का झटका झेल सकती है, लेकिन इसकी हकीकत प्राधिकरण को नहीं पता। इसकी बड़ी वजह ये है कि बिल्डर प्राधिकरण को आईआईटी से एप्रूव स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देकर मानचित्र को पास करवा लेता है।

निर्माण के दौरान प्राधिकरण की टीम वहां नहीं जाती। निर्माण के बाद इसी रिपोर्ट के आधार पर बिल्डर प्राधिकरण से कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल कर खरीदारों को कब्जा देता है। अप्रैल में इन्हीं खामियों को दुरुस्त करने के लिए प्राधिकरण ने स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी बनाई। अब बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट तभी जारी किया जाएगा जब वह स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट प्राधिकरण में जमा करेगा।

दिल्ली-एनसीआर में भूकंप केंद्र रहा तो क्या होगा

यह ऑडिट उसे प्राधिकरण के पैनल में शामिल सात एजेंसियों से कराना होगा। इसके लिए फीस भी बिल्डर को भरनी होगी। नोएडा में भले ही बनी हुई इमारत या परियोजनाएं सात से लेकर आठ रिक्टर स्केल का झटका झेल सकती है, लेकिन यदि भूकंप का केंद्र नोएडा या दिल्ली-एनसीआर में रहता है और उसकी क्षमता छह से ज्यादा रहती है। तो वाइब्रेशन के कारण यहां भारी नुकसान हो सकता है।

शहर में प्राधिकरण की ओर से जो भी परियोजनाओं को निर्माण कराया जा रहा है, वह सभी भूकंप की दृष्टि से भले ही सिसमिक जोन-4 में आती है, लेकिन यहां की परियोजनाओं का निर्माण सिसमिक-जोन 5 के अनुसार किया जा रहा है। यह 8 रिक्टर स्केल का झटका झेल सकती है। 7 रिक्टर स्केल का झटका की ताकत 6 से करीब 10 गुना और 8 की ताकत 6 से 100 गुना ज्यादा होती है।

तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर, दो बाइक सवारों की इलाज के दौरान मौत; एक की हालत गंभीर

गुरुग्राम के गांव वजीरपुर के नजदीक पटौदी रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी इससे बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया जहां इलाज के दौरान दो ने दम तोड़ दिया। वहीं एक शख्स अब भी गंभीर हालत में है। तीन बाइक सवार बिहार के मूल निवासी हैं।

गुरुग्राम। गुरुग्राम के गांव वजीरपुर के नजदीक पटौदी रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, इससे बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोग वहां जुट गए और घायलों को नजदीक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ ही देर बाद इलाज के दौरान दो बाइक सवारों दम तोड़ दिया। तीसरे की हालत भी गंभीर बनी हुई है। मृतकों की पहचान बिहार के छपरा जिले में गांव ढारीपुर माढ़ के रहने वाले अरुण राम एवं वकील राम के रूप में की गई है। जबकि घायल शख्स की पहचान बिहार के ही मुजफ्फरपुर जिले में गांव मुशहर लोचनपुर के रहने वाले नवीन राम के रूप में की गई। शिकायत के आधार पर सेक्टर-10ए थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक पुलिस उस ट्रक का पता नहीं लगा सकी है जिससे टक्कर हुई।

बदमाशों के हौसले बुलंद, बैंक कर्मी से नकदी व आईफोन लूट कर हुए फरार, पुलिस पर की फायरिंग

इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर-15 में अटल चौक पुलिस चेकपोस्ट के पास दो बदमाशों ने भारतीय स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक को उन्हीं के कार में अगवा करके नकदी और आईफोन लूट लिया। विरोध करने पर पिस्टल की बट से वार कर उनका सिर फोड़ दिया। रास्ते में प्रबंधक द्वारा लगातार हार्न बजाने पर पुलिस ने पीछा किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

साहिबाबाद। इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर-15 में अटल चौक पुलिस चेकपोस्ट के पास दो बदमाशों ने भारतीय स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक को उन्हीं के कार में अगवा करके नकदी और आईफोन लूट लिया। विरोध करने पर पिस्टल की बट से वार कर उनका सिर फोड़ दिया। रास्ते में प्रबंधक द्वारा लगातार हार्न बजाने पर पुलिस ने पीछा किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की।

प्रबंधक को छुड़ाकर एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा फरार हो गया। वसुंधरा सेक्टर दो के भारतीय स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक विक्रमेंद्र प्रताप सिंह बृहस्पतिवार देर शाम ईको कार से साथी अमित सैनी को प्रह्लादगढ़ी छोड़ने गए थे। वापस लौटते समय आनलाइन वीसी में जुड़ गए।

वसुंधरा सेक्टर 15 में कार खड़ी कर वीसी करने लगे। कार की खिड़की का शीशा खुला था। तभी दो बदमाश पैदल ही उनके पास आए। एक बदमाश ने माथे पर पिस्टल सटा दी। दूसरा बदमाश परिचालक वाली खिड़की से कार में बैठ गया। दूसरे बदमाश ने उन्हें धक्का दिया और चालक की सीट पर बैठ गया। दोनों बदमाशों ने उन्हेंसीट के बीच में बैठा लिया।

बदमाशों से उनसे पांच हजार रुपये और आईफोन लूट लिया। कार सहित उन्हें अगवा करके भागने लगे। अटल चौक पुलिस चेकपोस्ट के पास पुलिस को देखकर उन्होंने किसी तरह पैर से लगातार हार्न बजा दिया। बदमाशों ने गुस्से में आकर उनके सिर पर पिस्टल मारकर घायल कर दिया।

बाइक सवार दो पुलिसकर्मी कार के पास पहुंचे तो दोनों बदमाश प्रबंधक को कार सहित छोड़कर पैदल ही भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने पीछा किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान सड़क पर राहगीर चल रहे थे। एक राहगीर गोली लगने से बाल-बाल बचा। दोनों बदमाश अलग-अलग रास्ते से भागे।

एक बदमाश निर्माणाधीन इमारत की ओर से सहायक पुलिस आयुक्त के कार्यालय की ओर भागा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और उसे दबोच लिया। उसकी पहचान मुरादनगर के आनंद के रूप में हुई है। वह यहां भोवापुर में किराए पर रहता था।

उसका साथी फरार हो गया। आनंद ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि फरार बदमाश मंडोली, दिल्ली का गौरव है। घायल प्रबंधक को जिला संयुक्त अस्पताल में उपचार चल रहा है। एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे की तलाश की जा रही है। लूटे गए रुपये और आइफोन बरामद हो गया है।

कन्या विवाह फर्जीवाड़ा: रिपोर्ट दर्ज कराने वाला अफसर बना आरोपित, अपात्रों का पंजीकरण कर घोटाला करने का है आरोप

गाजियाबाद में कन्या विवाह योजना में फर्जीवाड़े की रिपोर्ट दर्ज कराने वाला श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुभाष भारती अपने ही दर्ज कराए मुकदमे में आरोपित बन गया है। इस मामले में दर्ज पांच मुकदमों की संयुक्त रूप से विवेचना की जा रही है जिसमें पांच में सुभाष भारती के साथ उप श्रमायुक्त कार्यालय के लिपिक रोहित को भी आरोपित बनाया गया है।

गाजियाबाद। कन्या विवाह योजना में फर्जीवाड़े की रिपोर्ट दर्ज कराने वाला श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुभाष भारती अपने ही दर्ज कराए मुकदमे में आरोपित बन गया है।

इस मामले में दर्ज पांच मुकदमों की संयुक्त रूप से विवेचना की जा रही है, जिसमें पांच में सुभाष भारती के साथ उप श्रमायुक्त कार्यालय के लिपिक रोहित को भी आरोपित बनाया गया है। फिलहाल वह फरार है, जबकि सुभाष भारती को 26 सितंबर को मुरादाबाद में 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया था। वह बरेली के जिला कारागार में बंद है। गाजियाबाद पुलिस जल्द ही उसका बी वारंट लेकर बरेली जेल में पूछताछ करने जाएगी। जरूरत पड़ी तो उसे पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर भी पूछताछ की जा सकती है।

पात्र खोजने के बजाय दलाल ढूंढे

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के निर्देश पर इस योजना में निर्धन परिवारों को ढूंढकर उनकी बेटियों की शादी करानी थी, जिसमें 75 हजार रुपये की आर्थिक सहायता के साथ जरूरी सामान भी दिया गया।

आरोप है कि आरोपित अधिकारी ने पात्रों को नहीं ढूंढा और लिपिक रोहित के जरिये गगन एन्क्लेव में रहने वाली पुष्पा सिंह से शादीशुदा लोगों के आवेदन मंगवाए और फर्जी दस्तावेजों का बिन सत्यापन पंजीकरण कर फर्जीवाड़ा किया।

अधिकारी और लिपिक को एक अक्टूबर को गिरफ्तार पुष्पा से पूछताछ के बाद आरोपित बनाए गए हैं। जांच में सामने आया है कि जोड़े को मिले 75 हजार रुपये में से 25 हजार रुपये पुष्पा ले लेती थी, जो बाद में इनके बीच बराबर बांटा जाता था।

ऐसे किया फर्जीवाड़ा

पुष्पा के साथ रामवीर, उसकी बेटी स्वाति व शिल्पी गिरफ्तार की गई थीं। शिल्पी ने पति योगेश से दोबारा शादी की थी और स्वाति की शादी उसके बहनोई अमरदीप से कराई गई थी। अधिकांश मामले दोबारा शादी के हैं। भोजपुर के अनुज व अंजलि, नंदग्राम की संजीदा व हिना को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। छह लोगों की पुलिस तलाश कर रही है।

दैनिक जागरण ने उजागर किया था फर्जीवाड़ा कन्या विवाह योजना के तहत पिछले साल गाजियाबाद में तीन हजार जोड़ों की शादी हुई थी। करीब दो माह पूर्व दैनिक जागरण ने इस योजना में फर्जीवाड़ा कर पैसों की बंदरबाट के मामले को उजागर किया था, जिसके बाद किसान संगठनों ने इस मामले को प्रशासन के समक्ष उठाया।

लगातार शिकायत के बाद थाना सिहानी गेट में पांच केस दर्ज कराए गए थे, जिनमें से तीन सुभाष भारती की ओर से थे। सुभाष भारती का तबादला कुछ दिन पहले मुरादाबाद हुआ था, जहां वह पेट्रोल पंप पर अनियमितताओं के मामले में घूस लेने के आरोप में पकड़ा गया था।

एसीपी नंदग्राम, रवि कुमार सिंह ने बताया कि सुभाष भारती व रोहित को कन्या विवाह योजना में फर्जीवाड़े का आरोपित बनाया गया है। रोहित समेत अन्य को तलाश रहे हैं। बी वारंट लेकर सुभाष के खिलाफ मिले साक्ष्यों के अनुरूप पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करेंगे।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य के गठन का मुद्दा उठाना हकीकत

अजय कुमार

बात केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान की कि जाये तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और हाईकोर्ट प्रयागराज में है, ऐसे में पश्चिमी यूपी के निवासियों को हाईकोर्ट की दूरी तय करने में काफी समय लग जाता है।

आम चुनाव से पूर्व एक बार फिर अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग उठने लगी है। मांग भी बीजेपी के सांसद द्वारा किया जाना और भी आश्चर्यजनक लगता है। दरअसल, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान के पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग के बयान से राजनीति गरमा गई है। वैसे राजनीति के कुछ जानकार इसे किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को हो रहे सियासी नुकसान को पाटने के तौर पर देख रहे हैं। जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उसकी काट के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है।

बात बालियान की कि जाये तो उन्होंने कहा कि उप्र की राजधानी लखनऊ है और हाईकोर्ट प्रयागराज में है, ऐसे में पश्चिमी यूपी के निवासियों को हाईकोर्ट की दूरी तय करने में काफी समय लग जाता है। इसलिए पश्चिमी यूपी को अलग राज्य घोषित कर मेरठ को इसकी राजधानी बनाया जाए ताकि यहां के नागरिकों की समस्या का समाधान हो सके। छपरौली से भाजपा के पूर्व विधायक सहेंद्र सिंह रमाला ने भी केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनवाने के बयान का समर्थन किया। पूर्व विधायक ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हर हाल में बनना चाहिए और इसकी राजधानी मेरठ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनने से क्षेत्र में खुशहाली आएगी और विकास के रास्ते खुलेंगे। यह देश का सबसे अच्छा और समृद्ध प्रदेश होगा।

लेकिन संजीव बालियान की मांग का बीजेपी नेताओं ने ही विरोध शुरू कर दिया। वहीं आरएलडी और समाजवादी पार्टी के ओर से भी प्रतिक्रिया आई है।

संजीव बालियान की मांग पर आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह छोटे राज्यों के पक्ष में थे। उन्होंने हरित प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल की बात की थी। इसके साथ ही विदर्भ और अन्य राज्यों की बात अपने वक्त पर करते थे, लेकिन बीजेपी राज्यों का बंटवारा नहीं करने जा रही है, वो चुनाव को देखकर डरी हुई है। पश्चिम में रालोद और जयंत चौधरी की लोकप्रियता बढ़ी है लिहाजा बीजेपी डर कर ऐसे बयान दे रही है।

वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने संजीव बालियान के बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। अब संगीत सोम के इस बयान पर त्रिलोक त्यागी ने पलटवार करते हुए कहा है कि ऐसे बयान मंदबुद्धि और कुबुद्धि के लोग देते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के ओर से सांसद एसटी हसन भी इस जुबानी जंग में आ गए हैं। उन्होंने पश्चिमी यूपी की मांग पर कहा कि हम चाहेंगे कि विभाजन नहीं हो। संजीव बालियान का ये बयान पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है, वो इसमें कोई अपना समीकरण देख रहे होंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि आप कह रहे हैं पश्चिमी राज्य, उत्तर प्रदेश के दो हिस्से करके बनने चाहिए। ये आप कह किससे रहे हैं- सपा, कांग्रेस या आरएलडी से। आप सत्ता में हैं तो साढ़े नौ साल में क्यों नहीं बनाया है। उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, आप प्रस्ताव मंगा लीजिए और बनाईए। हम आपका स्वागत करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि बनाना तो आपको है और बीजेपी को बनाना है तो आप बनाते क्यों नहीं हैं। कुल मिलाकर सामने हार देखकर और दीवार पर लिखी हुई इबारत पढ़कर पश्चिमी यूपी के नाम पर जुमला फेंका जा रहा है।

साहब...शौकीन ने बेटी की जिंदगी खराब कर दी, फांसी नहीं दिला सकते तो हमें सौंप दें...न्याय कर देंगे

पिता संजय ने बताया कि शौकीन उनपर दिव्या का स्कूल बदलने के लिए दबाव बनाता था। कुछ दिन पहले दिव्या के स्कूल की एक छात्रा प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। इस बारे में शौकीन को पता चला तो वह स्कूल जाने के लिए दिव्या से मना करने लगा। इसको लेकर कुछ दिन पहले संजय और शौकीन में कहासुनी भी हुई थी।

मोदीनगर। साहब... फूल सी बच्ची दिव्या की शौकीन ने जिंदगी खराब कर दी। उसके शरीर पर गंभीर चोट हैं। आगे उसका जीवन कैसे चलेगा, अभी इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। शौकीन को फांसी की सजा दिलाना। यदि पुलिस उसे फांसी नहीं दिला सकते तो उसे हमें सौंप दें। हम उसका न्याय कर देंगे। उसकी जो सजा कानून हमें देगा हम उसे भुगतने के लिए तैयार हैं। अस्पताल में दिव्या जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। कभी सोचा भी नहीं था कि दिव्या के साथ ऐसा हो जाएगा। ये बातें दिव्या के पड़ोसी भीम सिंह ने डीसीपी ग्रामीण के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर कहीं।

ये है मामला

गाजियाबाद के मोदीनगर की जगतपुरी कॉलोनी में दिनदहाड़े एक मुस्लिम पड़ोसी शौकीन ने स्कूल की छात्रा पर तलवार से वार कर दिया। घटना गुरुवार शाम की है। आरोपी कॉलोनी में तलवार लहरा रहा था, तभी लोगों को आता देख वह फरार हो गया। किशोरी की हालत गंभीर बनी हुई है और घटना के बाद क्षेत्र में सांप्रदायक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है।

मिला कार्रवाई का भरोसा

डीसीपी ने कार्रवाई का भरोसा देकर उन्हें शांत किया। दादी राजबाला रोते हुए कह रही थी कि पिछले दो साल से शौकीन घर पर ही खाना खाता था। कई बार दिव्या ने ही उसे लिए खाना तैयार किया। वह ही शौकीन को खाना परोसती थी। रक्षाबंधन पर दिव्या ने शौकीन को राखी भी बांधी थी। वह उसे भाई मानती थी। लेकिन आरोपित के जहन में उसके लिए कितनी नफरत थी, इसका अंदाजा कभी लग ही नहीं सका।

स्कूल बदलने के लिए बनाता था दबाव

पिता संजय ने बताया कि शौकीन उनपर दिव्या का स्कूल बदलने के लिए दबाव बनाता था। कुछ दिन पहले दिव्या के स्कूल की एक छात्रा प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। इस बारे में शौकीन को पता चला तो वह स्कूल जाने के लिए दिव्या से मना करने लगा। इसको लेकर कुछ दिन पहले संजय और शौकीन में कहासुनी भी हुई थी। जिसके बाद स्कूल बदलने पर सहमति बन गई थी। इतना ही नहीं, वह उसे ट्यूशन में भी अकेले नहीं जाने देता था। वह उसे हर बात में टोकता था।

हिंदू संगठनों ने की सुरक्षा की मांग

घटना की सूचना पर हिंदू संगठन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचें और पीड़ित परिवार को सुरक्षा दिलाने की मांग की गई। हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व महामंत्री नीरज शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे पदाधिकारियों ने जमकर हंगामा भी किया। घटना को लेकर उनमें आक्रोश भी दिखा।

इन इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलता है भरपूर सामान रखने का स्पेस ओला से लेकर हीरो तक इस लिस्ट में शामिल

आज हम आपके लिए बेस्ट बूट स्पेस से लैस इलेक्ट्रिक स्कूटर की लिस्ट लेकर आए हैं।इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस के साथ ही ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है । इस स्कूटर में कुल 43 लीटर का बूट स्पेस मिलता है सेफ्टी के मामले में भी यह काफी दमदार है। भारतीय बाजार में सबसे अधिक सेल इलेक्ट्रिक स्कूटर में ओला की ही होती है ।

आज के समय में आसपास जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे बेस्ट ऑप्शन है । इसमें न केवल आपके पैसों की बचत होती है बल्कि समय की भी बचत होती है। अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर से कहीं भी आते जाते हैं और सामान रखने की आपको आदत है तो आज हम आपके लिए बेस्ट बूट स्पेस से लैस इलेक्ट्रिक स्कूटर की लिस्ट लेकर आए हैं। इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस के साथ ही ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है । इस स्कूटर में कुल 43 लीटर का बूट स्पेस मिलता है सेफ्टी के मामले में भी यह काफी दमदार है। इसके साथ ही इसकी रेंज भी काफी बढ़िया है।

ओला एस 1 प्रो

भारतीय बाजार में सबसे अधिक सेल इलेक्ट्रिक स्कूटर में ओला की ही होती है ।आपको बता दे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको कल 36 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा।

ओला एस1 प्रो जेन 2 एयर

हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर ओला का ही स्कूटर है। यह नए और शानदार टेक्नोलॉजी से लैस है इसमें आपको काफी स्टोरेज भी मिल जाता है। इस स्कूटर में कुल 34 लीटर का स्टोरेज मिलता है।

सिम्पल वन

यह इलेक्ट्रिक स्कूटर खोल दो बैटरी बैक के साथ आता है इसके बाद भी इस स्कूटर में आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। इसमें कुल 30 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

हीरो वीदा वी 1

हीरो का यह सबसे के फायदे इलेक्ट्रिक स्कूटर है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 26 लीटर तक का बूट स्पेस मिल जाएगा। स्टोरेज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप इसमें आराम से एक हेलमेट तो रख ही सकते

ये हैं सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप-5 ईवी ब्रांड पिछले महीने बेचीं इतनी इलेक्ट्रिक कारें

इस साल इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश के लिए स्वच्छ और हरित परिवहन भविष्य बनाने के लक्ष्य के साथ चार पहिया वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ यह तेजी पर है। हालांकि, अगस्त 2023 में इलेक्ट्रिक चार-पहिया वाहनों की बिक्री में काफी गिरावट आई। इस सेगमेंट में पिछले महीने की तुलना में 13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यहां हम आपको बता रहें हैं कि अगस्त 2023 में किन वाहन निर्माताओं ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की।

Tata Nexon EV Facelift –

टाटा मोटर्स ने अगस्त 2023 में भी मार्केट लीडर की स्थिति बरकरार रखी। उसके बाद एमजी मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्थान रहा। यानी टॉप-3 पोजिशन पहले की तरह बरकरार हैं। इस बीच, ह्यूंदै मोटर्स और पीसीए ऑटोमोबाइल्स ने क्रमशः चौथी और पांचवीं पोजिशन हासिल की।

Tata Tiago EV –

टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए अलग प्लेटफार्म Tata.ev की शुरुआत की है। इसके तहत कंपनी अपनी तीन इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री करती है। जिनके साथ पिछले महीने टाटा मोटर्स ने 4,613 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की। जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है।

MG Comet EV

सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बेचने वाले वाहन निर्माताओं की सूची में एमजी मोटर्स दूसरे नंबर रही। अगस्त के महीने में कंपनी अपने इलेक्ट्रिक कारों की 1,150 यूनिट्स की बिक्री करने में कामयाब रही। एमजी मोटर इस समय भारतीय बाजार में दो इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री करती है। जिनमें पहली एमजी जेडएस ईवी और दूसरी एमजी कॉमेट है, जो इस समय सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार भी है।

Mahindra XUV400 –

इस सूची में महिंद्रा एंड महिंद्रा तीसरे नंबर पर रही। वाहन निर्माता ने पिछले महीने 376 यूनिट्स इलेक्ट्रिक कारें बेचीं। महिंद्रा इस समय भारतीय बाजार में फिलहाल एकमात्र इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा एक्सयूवी400 की बिक्री करती है।

Hyundai Kona Electric

चौथे नंबर पर ह्यूंदै मोटर काबिज हुई। वाहन निर्माता इस समय कोना इलेक्ट्रिक और आयोनिक 5 इलेक्ट्रिक एसयूवी बेचती है। कंपनी इन दोनों ईवी की 182 यूनिट्स की बिक्री करने में सफल रही।

eC3 –

सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री करने वाले वाहन निर्माताओं की सूची में पांचवे नंबर पर सिट्रोएन रही। अगस्त के महीने में कंपनी ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार सिट्रोएन ईसी3 की 111 यूनिट्स की बिक्री की है।

त्योहारी सीजन से पहले सस्ती हो गई ये Electric SUV , 2.3 लाख रुपये कम हुई कीमत

MG ZS EV: एमजी जेडएस ईवी (MG ZS EV) 3 ट्रिम लेवल- एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव प्रो में उपलब्ध है. अब इनकी कीमत क्रमशः 22.88 लाख रुपये, 24.99 लाख रुपये और 25.89 लाख रुपये है.

एमजी मोटर इंडिया ने 2020 में भारतीय बाजार में ZS EV को लॉन्च किया था. एसयूवी को खरीदारों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली. पिछले साल एमजी ने बड़े बैटरी पैक और कई नए फीचर्स के साथ फेसलिफ्टेड ZS EV पेश की थी. अब 100वीं सालगिरह का जश्न मनाते हुए एमजी मोटर इंडिया ने ZS EV की कीमतों में कटौती की है. एमजी जेडएस ईवी की कीमतों में 2.3 लाख रुपये तक की कटौती हुई है. यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 3 ट्रिम लेवल- एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव प्रो में उपलब्ध है. इसके बेस वेरिएंट की कीमत अब 22.88 लाख रुपये हो गई है, जो पहले से 50,000 रुपये कम है.

कीमत

वहीं, MG ZS EV एक्सक्लूसिव वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा कटौती हुई है, जो 2.3 लाख रुपये की है. इस वेरिएंट की कीमत अब 24.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है. एमजी ने टॉप-स्पेक एक्सक्लूसिव प्रो वेरिएंट की कीमत में 2 लाख रुपये की कटौती की है, जिससे इसकी कीमत 25.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है. एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव प्रो ट्रिम्स को आइकॉनिक आइवरी इंटीरियर फिनिश विकल्प के साथ पेश किया गया है.

ADAS से लैस

गौरतलब है कि ZS EV में ADAS लेवल-2 भी आता है. ADAS तकनीक के तहत स्पीड असिस्ट सिस्टम, लेन फ़ंक्शन, रियर-ड्राइव असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और फ्रंट कोलिजन वार्निंग सहित और कई अन्य फीचर्स मिलते हैं. एक प्रेस नोट में एमजी ने कहा, भारत में लॉन्च के बाद से ₹इलेक्ट्रिक एसयूवी 25 करोड़ किलोमीटर से अधिक चल चुकी (सभी बिक्री हुई एसयूवी) है और CO2 उत्सर्जन में लगभग तीन करोड़ किलोग्राम बचाया गया है.₹

बैटरी और रेंज

MG ZS EV में 50.3kWh बैटरी पैक और फ्रंट-एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है. इलेक्ट्रिक मोटर 174bhp और 280Nm जनरेट करती है. दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 461 किमी की रेंज दे सकती है. ZS EV का मुकाबला Hyundai Kona EV, Tata Nexon EV और Mahindra XUV400 से है.

वैश्विक संदर्भ में अंबेडकर की प्रासंगिकता

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

मैरीलैंड में अंबेडकर की मूर्ति स्थापना का संकेत क्या है? भारत को भी उत्तरी अमेरिका में अफ्रीकी मूल के नागरिकों व इंडियन के अधिकारों के लिए अपनी आवाज विश्वमंचों पर उठानी चाहिए'

डा. भीमराव रामजी आम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा यूएसए के मैरीलैंड प्रान्त में लग रही है। आम्बेडकर के चिन्तन को लेकर दूसरे द्वीपों में भी चर्चा शुरू हुई है, यह सचमुच प्रसन्नता की बात है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आम्बेडकर के व्यक्तित्व के दो पक्ष हैं। चिन्तक का और दूसरा सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय नेतृत्व का। उन्होंने चिन्तक के रूप में भारतीय सामाजिक संरचना और व्यवस्था का गहरा अध्ययन किया। कालक्रम से उसमें घर कर गई विकृतियों की कारण मीमांसा की। यह कारण मीमांसा पश्चिमी समाजशास्त्रियों द्वारा भारतीय या हिन्दू समाज की विकृतियों के लिए स्थापित किए गए निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। उसका कारण आम्बेडकर की भारतीय दृष्टि थी और वे अपने समाज के सभी पक्षों को गोरे समाजशास्त्रियों से बेहतर जानते थे। इसका उन्होंने एकाध बार संकेत भी किया है। लेकिन आम्बेडकर कारण मीमांसा के बाद चुप नहीं बैठे। वे उसके निराकरण के लिए धरातल पर सक्रिय हो गए। अपने इन आन्दोलनों में उन्हें कहीं सफलता मिली और कहीं असफलता, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब उन्हें विभाजन के बाद शेष भारत के लिए संविधान बनाने का अवसर मिला तो उन्होंने अनेक सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने के विधिक रास्ते तलाश किए। उसके कारण वर्तमान में भारतीय/हिन्दू समाज में बहुत परिवर्तन सहज ही दिखाई देता है। लेकिन दुनिया के दूसरे छोर पर भी सामाजिक व्यवस्थाओं में प्रजाति व रंग के आधार पर अमानवीय भेदभावपूर्ण व्यवहार का साम्राज्य व्याप्त है। अमानवीय व्यवहार का यह साम्राज्य उसी क्षेत्र में व्याप्त है जिसमें कभी 'स्टैच्यू आफ लिबर्टी' स्थापित कर स्वतंत्रता व समानता की घोषणा की गई थी। उसी क्षेत्र यानी उत्तरी अमेरिका में अब आम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की जा रही है। क्या यह उत्तरी अमेरिका में अफ्रीकी समुदाय और इंडियन समुदाय (उत्तरी अमेरिका में इंडियन वे हैं जिनके पूर्वज पन्द्रह बीस हजार साल पहले जम्बूद्वीप/एशिया से साइबेरिया होते हुए वहां पहुंचे थे) से गोरे लोगों द्वारा किए गए भेदभाव के खिलाफ एक नए संघर्ष की शुरुआत मानी जाए? इसकी शुरुआत आम्बेडकर के रास्ते पर चल कर होगी? आम्बेडकर के संघर्ष का वह रास्ता जो अन्ततः तथागत बुद्ध के रास्ते से जाकर मिल जाता है। इंडियन को उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए व कनाडा में गए हुए बीस हजार साल हो गए हैं। उन्होंने इन प्रदेशों को आबाद किया। अपने कठिन परिश्रम से वहां बस्तियां आबाद की। जीवन मूल्यों के आधार पर परिवार व समाज की संरचना की। ऐसा समाज जो धरती को मां मानता था। लेकिन आज से पांच सौ साल पहले वहां स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस व पुर्तगाल इत्यादि से यूरोपीय लोग पहुंचे। इंडियन, जो अतिथि सत्कार को धर्म मानते थे, ने इनका हार्दिक स्वागत ही नहीं किया बल्कि उन्हें खाने के लिए अन्न, जल और आवास तक दिया। परन्तु इन गोरे लोगों ने जिनके जीवन मूल्य शोषण पर आधारित थे, इन इंडियन को गुलाम बनाया, उनका मतान्तरण किया, बहुत बड़ी संख्या में उनकी हत्या की और धीरे धीरे उन्हें उनके देश में ही दोयम दर्जे के नागरिक बना दिया। उन्हें 'रिजर्व' में ही सीमित कर दिया। आज उनका उत्तरी अमेरिका के देशों की सत्ता में कोई स्थान नहीं है। गोरे उन्हें हिकारत से देखते हैं। ऐसा ही एक दूसरा समुदाय अफ्रीकियों का है जिनका उत्तरी अमेरिका में आगमन बड़ी मुश्किल से दो तीन सौ साल पहले हुआ। लेकिन वे अपनी इच्छा से इंडियन की तरह साइबेरिया के रास्ते उत्तरी अमेरिका नहीं पहुंचे थे, बल्कि उन्हें अफ्रीकी देशों से गोरों की कम्पनियां धोखे से लेकर आई थीं। ये कम्पनियां इन अफ्रीकी लोगों की खरीद फरोख्त का काम अखबारों में विज्ञापन देकर करती थीं। इन अफ्रीकियों को बेचने के लिए उसी प्रकार बाजार लगता था, जैसे बकरी भेड़ बेचने के लिए बाजार सजता है। इस प्रकार बिके हुए अफ्रीकी पुरुष स्त्रियां अपने मालिकों की सम्पत्ति मानी जाती थी। इतना ही नहीं, इन गुलामों के बच्चे भी उसी मालिक के गुलाम माने जाते थे। यहां तक कि 1865 तक आते आते अफ्रीकियों को गुलाम बनाने के प्रश्न पर यूएसए ही टूट गया। कान्फेडरेट स्टेट्स आफ अमेरिका के नाम से एक हिस्सा टूट कर नया देश बन गया। यह लड़ाई लम्बी चली। अन्ततः कान्फेडरेट स्टेट्स आफ अमेरिका की पराजय हुई। कहा गया कि अफ्रीकियों को गुलाम बनाने की प्रथा कम से कम वैधानिक रूप से खत्म कर दी गयी। लेकिन अमेरिकी इस प्रथा के पक्ष में इस कदर थे कि उन्होंने अपने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को, जिन पर शक था कि वे अफ्रीकियों को गुलाम बनाने के खिलाफ हैं, मार ही दिया। उनकी हत्या से गोरे लोगों की अन्तरात्मा जागेगी और वे अफ्रीकी मूल के नागरिकों को अपने बराबर अधिकार दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफ्रीकी मूल के नागरिकों को वोट देने का अधिकार तब भी नहीं मिल पाया। इस अधिकार के लिए तो उन्हें और भी लम्बा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन अफ्रीकी मूल की महिलाओं को तो वोट देने का मुकम्मल अधिकार 1965 के आसपास ही मिल पाया। जाहिर है सभ्य देशों में इससे अमेरिका की बदनामी होती। उसे धोने के लिए 1886 में उन्होंने बाकायदा 'स्वतंत्रता की देवी' भी स्थापित कर दी। लेकिन क्या इससे अफ्रीकी मूल के नागरिकों और 'इंडियन' को गोरे लोगों के अत्याचारों से स्वतंत्रता मिल गई? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इंडियन अब भी अपने लिए सरकार द्वारा निर्धारित 'रिजर्व' में ही रहने के लिए विवश हैं। इन रिजर्व में जाने के लिए सडक़ें तक नहीं हैं। वहां किसी प्रकार की अन्य सुविधाएं भी नहीं हैं। अफ्रीकी मूल के नागरिक शहरों के जिन हिस्सों में रहते हैं, वहां गोरे रहना तो दूर, नजदीक जाना भी पसन्द नहीं करते। उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता है। उत्तरी अमेरिका में कोलम्बस को यूरोप के गोरे लोगों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इंडियन मानते हैं कि अमेरिका में कोलम्बस के आने से इंडियन की ग़ुलामी की शुरुआत हुई। गोरे अमेरिकी कोलम्बस को अपना राष्ट्रीय नायक मानते हैं। जिस दिन उसने अमेरिका की धरती पर पांव रखा था, उस दिन को यूएसए सरकार राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाती है। लेकिन पिछले कुछ साल से 'इंडियन' इस दिन को ग़ुलामी के दिन के तौर पर मनाते हैं। इतना ही नहीं अब वे इस दिन सार्वजनिक स्थानों पर लगी कोलम्बस की मूर्तियों को तोड़ते हैं, उसका मुंह काला करते हैं। कुछ स्थानों पर तो व्हाइट हाऊस की सरकार ने कोलम्बस की मूर्तियों को उठा कर अजायब घर में रखवा दिया है। यूएसए और कनाडा में अभी भी अफ्रीकी मूल के नागरिक और इंडियन अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछली शताब्दी में महात्मा गान्धी ने दक्षिण अफ्रीका में ही गोरे लोगों द्वारा भारतीयों से किए जा रहे भेदभाव के खिलाफ अहिंसक संघर्ष किया था। अन्याय के खिलाफ संघर्ष का उनका अपना तरीका था। इसकी यूरोप में कुछ स्थानों पर चर्चा भी हुई। फ्रांस के रोम्यां रोलां ने तो इस पर विस्तार से लिखा भी। गान्धी जी ने तो अंग्रेजों के खिलाफ लम्बा संघर्ष भारत में भी किया। सामाजिक व्यवस्थाओं के खिलाफ गान्धी जी भी मैदान में थे। आम्बेडकर भी यही संघर्ष कर रहे थे। तरीका दोनों का अलग अलग था। ऊपर से दोनों अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे। लेकिन जैसा कि हिन्दी के साहित्यकार मोहन राकेश ने कभी लिखा था, जो ऊपर से अलग दिखाई देते हैं, वे भीतर से कहीं न कहीं जुड़े होते हैं। आज हमारे बीच न गान्धी जी हैं और न ही आम्बेडकर हैं। लेकिन उनका रास्ता अभी भी है। यह भारत का रास्ता है। उत्तरी अमेरिका में इंडियन व अफ्रीकी मूल के नागरिक आज इक्कीसवीं सदी में भी भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। इस मरहले पर मैरीलैंड में भीमराव रामजी आम्बेडकर की मूर्ति स्थापना का संकेत क्या है? भारत को भी उत्तरी अमेरिका में अफ्रीकी मूल के नागरिकों व इंडियन के अधिकारों के लिए अपनी आवाज विश्वमंचों पर उठानी चाहिए। आम्बेडकर के संघर्षों से अफ्रीकी व इंडियन प्रेरणा ले सकते हैं।

संपादक की कलम से

गिरफ्तारी के निहितार्थ

दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येन्द्र जैन के बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सिसोदिया और संजय को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य आरोपित माना है। सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से जेल में हैं और अदालत के किसी भी स्तर पर उन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी गई है। सत्येन्द्र जैन करीब डेढ़ साल जेल में गुजारने के बाद फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत पर हैं। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के ये नेता प्रमुख चेहरे हैं, लिहाजा सवाल मौजू है कि इस कड़ी में अगला नंबर किसका होगा? क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल शराब घोटाले की साजिशों में संलिप्त पाए जाएंगे, क्योंकि सभी आपराधिक आरोपी उनके करीबी थे और उनसे मुलाकातें करते रहे थे? सांसद संजय सिंह का नाम प्रवर्तन निदेशालय के आरोप-पत्र में पहले से ही था, जिसे चुनौती देने की घुडक़ी सांसद ने जांच एजेंसी को दी थी। अंततः बुधवार, 4 अक्तूबर, को 10 घंटे की गहन पूछताछ और तलाशी के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब न्यायिक निर्णय अदालत के विचाराधीन है। जांच एजेंसी ने 100 करोड़ रुपए के 'मनी ट्रेरल' का जो खुलासा किया है अथवा संजय सिंह को जिन भ्रष्ट क्रियाकलापों के आधार पर आरोपित किया है, हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। यह दायित्व और विशेषाधिकार अदालत का है, लेकिन कुछ सवाल और संदेह जरूर किए जा सकते हैं। दिल्ली के कारोबारी दिनेश अरोड़ा भी शराब घोटाले के आरोपित हैं, लेकिन वह 'सरकारी गवाह' बन गए हैं, लिहाजा उन्होंने जो खुलासे किए हैं, उनके आधार पर जांच-पड़ताल स्वाभाविक है। संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा ने 'आप' के लिए चंदा जुटाने के कार्यक्रम क्यों आयोजित किए थे? सांसद के कहने पर ही 32 लाख रुपए का चेक तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को क्यों दिया गया?

संजय की मध्यस्थता पर ही सिसोदिया और दिनेश की मुलाकात एक रेस्तरां में क्यों कराई गई थी? क्या सिसोदिया ने शराब नीति का मसविदा दिनेश के साथ साझा किया था? यदि ऐसा है, तो गोपनीयता उल्लंघन का दोष भी लगता है। सबसे गंभीर और संदेहास्पद सवाल यह है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ कारोबारी दिनेश की मुलाकात, संजय सिंह की मौजूदगी में ही, क्यों कराई गई थी? इन सवालों के मद्देनजर संलिप्तता और मिलीभगत की आंच मुख्यमंत्री तक भी जाती लग रही है। सवाल यह भी है कि दक्षिण के कारोबारी समूह ने 100 करोड़ रुपए की जो कथित घूस दी थी, क्या उसमें 70 करोड़ रुपए विजय नायर और 30 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा को मिले? नायर 'आप' के संचार विभाग के प्रभारी थे। मुख्यमंत्री ने सत्यापित किया था कि नायर अपने ही आदमी हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है। 'सरकारी गवाह' ने यह भी खुलासा किया है कि संजय सिंह ने एक मामला सुलझाने में उनकी मदद भी की थी। बेशक 'आप' के किसी भी नेता ने रिश्वत के पैसे लिए अथवा नहीं, वही भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन आपराधिक कोशिशों में संलिप्त होना ही उन्हें 'आरोपित' बना देता है। इस गिरफ्तारी का संबंध संसद में अडाणी पर पूछे गए सवालों या प्रधानमंत्री मोदी के खुलेआम विरोध अथवा केजरीवाल की राजनीति से उपजी बौखलाहट नहीं है। प्रधानमंत्री या सत्तारूढ़ दल ऐसे विरोधों से डरा नहीं करते। यह 'आप' की हास्यास्पद राजनीति है। यह कुछ हद तक माना जा सकता है कि 2014 के बाद सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है। करीब 95 फफीसदी केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज कराए गए हैं। इस कालखंड में ईडी ने ही एक लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति और नकदी जब्त किए हैं। इन्हें अदालत में चुनौती दी जाती रही है। अंततः सीबीआई और ईडी सरीखी जांच एजेंसियां अदालत के प्रति जवाबदेह हैं। सांसद का मामला भर अदालत के सामने जाना है। वही रिमांड तय करेगी, लेकिन अहम सत्य यह है कि 'आप' जिस ईमानदारी और शुचिता की राजनीति करने आई थी, उस पर ढेरों सवाल लगे हैं और 'आप' के नेता बेनकाब होते जा रहे हैं। केजरीवाल या पार्टी प्रवक्ता कुछ भी बयानबाजी करते रहें।

राय

सतर्कता के प्रबंध जरूरी

यह माना जा सकता है कि किसी सिरफिरे ने धर्मशाला की दीवार पर विवादित और पृथकतावादी नारे लिख दिए, लेकिन इस जुर्रत के लिए कानून-व्यवस्था के पहरों से शिकायत तो रहेगी ही। खास तौर पर जब क्रिकेट वल्र्ड कप के लिए पुलिस के पहरे तैनात थे, तो ये सेंधमारी दीवारों पर खालिस्तान समर्थकों के हस्ताक्षर कैसे लिख गई। जाहिर है यह हरकत करके देश की अखंडता को चुनौती देने की निर्लज्ज कोशिश हो रही है और इसी कड़ी में दूसरी बार सीमा पार बैठे गुरपतवंत सिंह पुन्नू का संगठन अपना नाम चस्पां करने के लिए, धर्मशाला की दीवारों को चिंतित कर रहा है। इससे पहले तपोवन विधानसभा परिसर के बाहर खालिस्तानी झंडों की श्रृंखला दिखाई दी गई थी। इन दोनों घटनाक्रमों में कुछ बातें सामान्य हैं यानी हिमाचल में विखंडनकारी ताकतों के खलल की पैमाइश हो रही है। पंजाब से सटे इलाकों से बार-बार ऐसे षड्यंत्रकारी तत्वों की आमद हो रही है। ऐसे में हमारी अपनी निगरानी और पुलिस बंदोबस्त का ढर्रा वही पुराना है। हिमाचल की सीमाई संवेदना में केवल पंजाब के अराजक व पृथकतावादी तत्वों का खतरा नहीं, बल्कि कश्मीर समस्या की चुनौतियां तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चीन की संदेहास्पद हरकतें भी दिखाई देती हैं। इस लिहाज से हमने आज तक किया ही क्या। बेशक ऐसे घटनाक्रम को अपराध की शिनाख्त में कड़ाई से देखा भी गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय साजिशों पर नजर रखने के लिए पूरी प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा।

आज भी पुलिस महकमे को हिमाचली आचरण में देखा जाता है, जबकि इस प्रदेश में हर साल अपनी आबादी से तीन गुना लोग बाहर से आ रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जिन्हें हम पर्यटक मानकर स्वागत द्वार खड़े कर रहे हैं, वे हमारे शांत वातावरण को विचलित नहीं करेंगे। पर्यटन की खाल में हो रही घुसपैठ पहले भी कुछ अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों का सुराग दे गई है। प्रदेश में फैलता नशे का कारोबार इन तमाम साजिशों के जाल में एक सबूत की तरह मानव चरित्र को दूषित कर रहा है, तो देश विरोधी ताकतों के लिए पैसे के दम पर बरगलाने के लिए यह हथियार बन जाता है। ऐसे में हिमाचल को अपने पुलिस बंदोबस्त के नैन नक्श तथा प्रदर्शन के तौर तरीके बदलने चाहिएं। विडंबना यह है कि जो राज्य आगामी कुछ सालों में पर्यटक आगमन के आंकड़े को पांच करोड़ तक पहुंचाना चाहता है, उसके पास इनके ऊपर नजर रखने का कोई मैकेनिज्म नहीं। नतीजतन हमारे प्रवेश द्वार केवल स्वागत की मुद्रा में बाहर से आ रहे खतरों को नजरअंदाज कर रहे हैं। पर्यटकों के पंजीकरण तथा उनके भ्रमण को किसी ऐप के जरिए मानिटर करने की जरूरत है। हिमाचल में निजी वाहनों के जरिए जो समूह प्रवेश कर रहे हैं, उनकी पूर्ण पड़ताल तथा डे एंड नाइट पैट्रोलिंग न होने के कारण कई तरह के तत्व घूम रहे हैं। कम से कम ये दोनों व इससे पूर्व की विखंडनकारी घटनाओं से सबक लेते हुए हिमाचल को अपनी सतर्कता के लिए प्रयास तथा प्रबंध बढ़ाने ही पड़ेंगे। जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं हिमाचल के बार्डर एरिया में पहले से बीबीएन व नूरपुर को पुलिस जिला बनाने के अलावा कुछ और पुलिस जिले सिरमौर तथा ऊना में चिन्हित करने चाहिएं। सारे सीमांत पुलिस जिलों की एक बार्डर रेंज बना कर इनका मुख्यालय बीबीएन में एक अतिरिक्त डीजीपी के तहत संचालित करना होगा। पुलिस के बीबीएन मुख्यालय के तहत सीमांत चौकसी, नशे के खिलाफ सक्रिय भूमिका, पर्यटन प्रवेश की जांच परख तथा इंडस्ट्रियल सुरक्षा की जिम्मेदारी देनी होगी। इसी के साथ प्रदेश में शिमला, धर्मशाला, मंडी व सोलन जैसी शहरी आबादी के लिए पुलिस आयुक्तालयों का गठन करते हुए इसके साथ ग्रामीण पुलिस व्यवस्था को भी अमली जामा पहनाना होगा। पुलिस महकमे को शिमला से बाहर निकाल कर कानून व्यवस्था की तमाम चुनौतियों का सामना करने की हिदायत मिल चुकी है।

महाविद्यालयों में खेल विंग कब?

भूपिंदर सिंह

हिमाचल प्रदेश के दूरदराज शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध खेल सुविधा के अनुसार खेल विंग खुलने चाहिए। कालेज स्तर पर अधिक से अधिक खेल विंग अगर खुलते हैं तो यहां की खेलों को अवश्य ही पंख लग सकते हैं'

विश्व के अधिकांश पदक विजेता खिलाड़ी महाविद्यालय स्तर से ही निकल कर आगे आते रहे हैं। जिन जिन देशों ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है वहां के शिक्षा संस्थानों के पास अच्छी खेल प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल ढांचा व प्रशिक्षक उपलब्ध रहते हैं। हिमाचल में महाविद्यालय स्तर पर खेल सुविधाओं का टोटा है। पंजाब की तरह यहां अभी तक महाविद्यालय स्तर पर खेल विंग विद्यार्थी खिलाडियों के लिए उपलब्ध नहीं है। पंजाब अपने विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न महाविद्यालयों व विश्वविद्यालय परिसरों में खेल सुविधा के अनुसार खेल विंग चलवा कर अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय खेलों की प्रतिष्ठित मौलाना अब्दुल कलाम ट्राफी पर कब्जा करता रहा है तथा खेल विंगों के माध्यम से ही उसने खेलों में श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त किया हुआ है। प्रतिभा व सुविधा के अनुसार हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में भी सरकार खेल विंग खोलती है तो भविष्य में हिमाचल के और अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कई महाविद्यालयों के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल ढांचा तैयार खड़ा यूं ही बेकार हो रहा है।

हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों में भी खेल विंग हो, इस कॉलम के माध्यम से पिछले दो दशकों से इस पर बहुत बार लिखा जा चुका है, मगर तत्कालीन सरकारों का रवैया उदासीन ही रहा है। खेल विंगों के लिए सरकार को न तो खेल ढांचा खड़ा करना पड़ता है और न ही नया छात्रावास बनाना पड़ता है। केवल खेल विशेष का प्रशिक्षक और खिलाडियों के लिए खुराक व रहने का प्रबंध करना होता है जो आसानी से बहुत कम धन राशि खर्च करके हो सकता है। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर, धर्मशाला, बिलासपुर व सरस्वती नगर में एथलेटिक्स के विंग आसानी से चल सकते हैं क्योंकि यहां तीन जगह सिंथेटिक ट्रैक हैं और चौथी जगह सरस्वती नगर में बन रहा है। हमीरपुर व धर्मशाला में साई विभिन्न खेलों में एक्सीलेंस सैंटर चला रही है, मगर यहां पर राष्ट्रीय पदक विजेताओं को ही प्रवेश मिलेगा। अच्छा होगा हिमाचल सरकार अपने प्रदेश से राष्ट्रीय पदक विजेता तैयार कर इन सैंटरों में भेजे। भारतीय खेल प्राधिकरण के शिलारू केन्द्र में भी दो सौ मीटर का सिंथेटिक ट्रैक बिछ गया है। वहां के नजदीकी विद्यालयों में एथलेटिक्स की नर्सरियां स्थापित हो सकती हैं। ऊना तथा मंडी में तैराकी के लिए तरणताल उपलब्ध हैं। शिलारू व ऊना में हॉकी की एस्ट्रोटर्फ बिछी हुई है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न खेलों का स्तर राज्य में खेल छात्रावासों के खुलने के बाद काफी सुधरा है। विद्यालय स्तर पर खेल छात्रावासों को आज से तीन दशक पहले शुरू कर दिया गया था। पपरोला के बास्केटबॉल खेल छात्रावास ने एक

समय तक अच्छे परिणाम दिए हैं।

हॉकी में माजरा स्कूली खेल छात्रावास की लड़कियों ने पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय स्कूली खेलों में हिमाचल प्रदेश को पदक तालिका में स्थान दिलाया है। यदि इन लड़कियों को एस्ट्रोटर्फ मिलता है तो बात कुछ और हो सकती है। स्कूल स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन सम्मानजनक खेल छात्रावासों के कारण रहता है। हिमाचल प्रदेश में स्कूली स्तर पर पपरोला में लडक़ों के लिए बास्केटबॉल, सुंदरनगर व नादौन में लडक़ों की हाकी, माजरा में लड़कियां के लिए हाकी में खेल छात्रावास चल रहे हैं। वालीबाल में स्कूली स्तर पर प्रशिक्षण का प्रबंध है। मतियाणा व रोहडू में लडक़ों को तथा कोटखाई में लड़कियों के लिए खेल छात्रावासों को वर्षों पहले से शुरू किया गया है। रोहडू में फुटबॉल का भी खेल छात्रावास है। इन छात्रावासों में अच्छे प्रशिक्षकों के साथ साथ खेल सुविधाओं में काफी सुधार की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय खेल प्राधिकरण ने तीस वर्ष पहले बिलासपुर व धर्मशाला में खेल छात्रावासों की शुरुआत की है। दो छात्रावास राज्य सरकार ने ऊना तथा बिलासपुर में चला रखे हैं। इन खेल छात्रावासों में अधिकांश बारह से चौदह वर्ष के खिलाड़ी बालक व बालिकाओं को ही प्रवेश मिलता है। स्कूल से निकल कर जब खिलाड़ी महाविद्यालय में प्रवेश ले रहा होता है तो उस समय उसकी उम्र अठारह वर्ष हो चुकी होती है। इसलिए इन खेल छात्रावासों में दाखिल होने के अवसर न के बराबर होते हैं। इसलिए हिमाचल में खिलाड़ी विद्यार्थी को स्कूल के बाद महाविद्यालय स्तर पर खेल विंग मिलना जरूरी हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में महाविद्यालय स्तर पर कोई भी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध न होने के कारण स्कूली स्तर पर सामने आई खेल प्रतिभाओं को या तो हिमाचल प्रदेश से पलायन कर पड़ोसी राज्यों के खेल विंगों की शरण लेनी पड़ती है या फिर असमय ही खेल को अलविदा कह कर गुमनामी के अंधेरे में खो जाना होता है। निजी स्तर पर नब्बे के दशक से सुंदरनगर में मुक्केबाजी तथा हमीरपुर में जूडो व एथलेटिक्स पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जो शुरू हुआ था उसी से मुक्केबाजी में परशुराम अवार्ड से सम्मानित पहले शिव चौधरी व अब आशीष चौधरी के लिए आधार मिला।

आज आशीष ओलंपिक खेल चुका है जो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। हमीरपुर से जूडो में परशुराम अवार्डी नूतन, एथलेटिक्स प्रशिक्षण कार्यक्रम से परशुराम अवार्डी पुष्पा ठाकुर ने तेज गति की दौड़ों में व संजो ठाकुर ने भाला प्रक्षेपण में राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश को पहचान दिलाई है। मोरसिंघी में चले हैंडबाल प्रशिक्षण कार्यक्रम से कई महिला खिलाडियों ने हिमाचल प्रदेश को कई बार पदकों से सजाते हुये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। पूरे संसार में खिलाडियों के लिए महाविद्यालय स्तर पर उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं क्योंकि यही उम्र होती है जहां से खिलाड़ी को स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की जरूरत होती है। महाविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि वह अपने स्तर पर भी खेल आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करे। हिमाचल प्रदेश के दूरदराज शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध खेल सुविधा के अनुसार खेल विंग खुलने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में महाविद्यालय स्तर पर अधिक से अधिक खेल विंग अगर खुलते हैं तो यहां की खेलों को अवश्य ही पंख लग सकते हैं।

हास्य चिंतन

दफ्तर में वसंत!

वे अपने पीले दांत दिखाते हुये आये थे मेरे पास। एक पल हंसते रहने के बाद बोले-'शर्मा फाइल से नजर हटाओ तो एक बात कहूं?' मैंने फाइल में नजर गड़ाये हुये ही कहा-'हां कहो, क्या बात है?' वे धीरे से फुसफुसाकर बोले-'सुनो कल वसंत पंचमी है। दफ्तर में भी आयेगा वसंत।' मैंने फाइल से नजरें हटाई, चेहरे पर हाथ फेरा और बोला हैरत से-'दफ्तर में भी आयेगा वसंत! क्या कह रहे हो यार, इससे पहले क्यों नहीं आया यह मुआ वसंत?' वे बोले-'शर्मा वसंत हर वर्ष आता है, लेकिन तुम कोई ध्यान ही नहीं देते। इसमें बेचारा वसंत क्या करे?' वे अभी तक अपने पीले दांतों से हंस रहे थे। मैं बोला-'हर साल आता है वसंत, तुमने कभी बताया तो नहीं। मैं भी देख लेता गोपाल बाबू उसे। सच कहूं मैंने वसंत को कभी नहीं देखा। सुना जरूर है कि वसंत में फूल खिल जाते हैं और पलाश दहकने लगता है। सुना तो यह भी है कि वसंत में पतझड़ भाग खड़ा होता है और पेड़ों में नयी कोंपलें आ जाती हैं। लेकिन वसंत दफ्तर में भी आयेगा, यह पहली बार सुना है।' गोपाल बाबू बोले-'तुमने सही सुना है शर्मा, प्रकृति वसंत में सोलह श्रृंगार करती है। फूल भी खिलते हैं। इस बार वसंत दफ्तर में आयेगा-मेरा मतलब वसंत जी आ रहे हैं, वे कल ज्वाइन करेंगे।' 'मेरी समझ में तुम्हारी एक भी बात नहीं आ रही। जरा खोलकर समझाओ वसंत जी कल ज्वाइन कैसे करेंगे?' मैं बोला। गोपाल बाबू अपनी मुस्कान को जारी रखते हुए बोले-'वे एक नम्बर के क्रप्ट हैं, मेरा मतलब वसंत जी से है। यदि उन्होंने कल ज्वाइन कर लिया है तो पूरा दफ्तर वसंत की खुशबू से भर उठेगा। सारे दिन फाइलों से सिरफोड़ी करने की जरूरत नहीं रहेगी शर्मा, वे मक्कार भी हैं। तुम्हारे चश्मे के नम्बर अब नहीं बढ़ेंगे। इसी चश्मे से हो जायेगा रिटायरमैंट।

पांच वर्ष में हम इतना कमा लेंगे कि गरीबी से निजात मिल जायेगी।' 'मेरी धडक़नों को क्यों तेज करने पर तुले हो गोपाल बाबू। मुझसे वसंत जी की सारी अन्तर्कथा जरा खोलकर समझाओ। मैं वसंत को अपनी झोली में भर लेना चाहता हूं।' मैंने कहा तो गोपाल बाबू ने अपनी मुस्कान को और अधिक सघन किया और बोले-'यह खुशखबरी मैं तुम्हें यों ही नहीं दूंगा, पहले चाय-समोसे का आर्डर तो देवो।' मैंने चपरासी से जब चाय-समोसा लाने को कहा तो वे अपनी बदबूदार सांसें मेरे मुंह में भरकर बोले-'वसंत जी हमारे नये अफसर हैं। सुना है कल वसंत पंचमी को यहां ज्वाइन करेंगे। भ्रष्टाचार के मामले में तीन बार सस्पैंड रह चुके हैं, लेकिन हर बार बेदाग निकल आये। उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो पूरे दफ्तर के पौ बारह हैं। मेरा मतलब वसंत ही वसंत। दोनों हाथों से लूटो। पूरा दफ्तर वसंतमय हो जायेगा।' मैं खुशी से नाच उठा और बोला-'गोपाल बाबू तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। यह खडूस ईमानदारी का पुतला वर्मा कब जा रहा है?' गोपाल बाबू मेरे कंधे थपथपाते हुये बोले-'घबराओ मत शर्मा, आज आफ्टरनून में रिलीव हो जायेगा और कल आ जायेगा दफ्तर में वसंत।

कल मनाओ जी भरकर वसंत पंचमी। क्रप्ट अफसर बड़े भाग्य से मिलता है। हमारे बच्चों के भाग्य में लिखा था यह वसंत। अपनी पूरी झोली भर लेना इस वसंत के राज में शर्मा।' मैंने कहा-'लो खाओ समोसे और पीवो गर्मागर्म चाय। अब उड़ायेंगे गुलछर्रे गोपाल बाबू। वर्षों में आया है यह वसंत। वह कविता तो सुनी होगी कि वीरों का कैसा हो वसंत? इस बार वसंत दफ्तर में खुद चलकर आया है। ये दिन बहार के हैं, इन्हें यों ही नहीं जाने देना। हम सब मिलकर भ्रष्टाचार का नंगा नाच करेंगे, तो क्या वसंत नहीं खिल उठेगा हमारे जीवन में भी।' गोपाल बाबू समोसे की जुगाली करते हुये और चाय सुडक़ते हुये बोले-'शर्मा दफ्तर में आया है वसंत, लूट लो इसको। मेरा मतलब दफ्तर का ऐसा ही होता है वसंत।'

पूरन सरमा

इनसाइड

गोल्ड लुढ़का तो चांदी हो गई महंगी, जानें आपके शहर में क्या है सोने-चांदी का भाव

शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई। वहीं आज चांदी की कीमत में तेजी आई है। ऐसे में अगर आप सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी है। इंटरनेशनल मार्केट में एक औंस सोने का कारोबार 1926 डॉलर में हुआ। वहीं चांदी 23 .19 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। जानिए आपके शहर में क्या है 10 ग्राम सोने की कीमत।

नईदिल्ली। सर्राफा बाजार में आज यानी शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट आई है। अगर आप भी सोने या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको एक बार जरूर चेक करना चाहिए कि आज आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर की कीमत क्या है?

सस्ता हुआ सोना

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 170 रुपये गिरकर 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, गुरुवार को गोल्ड 60,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। आज वैश्विक बाजारों में सोना गिरावट के साथ 1,925 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ कमोडिटी विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि घरेलू बाजारों में सोने की कीमत दबाव में आ गई, जिससे रुपये में मजबूती आई। मजबूत अमेरिकी मैक्रो डेटा के कारण कॉमेक्स सोने में गिरावट आई, जिससे यह उम्मीद जगी कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर लंबे समय के लिए उच्च रुख अपनाएगा।

क्या है चांदी का भाव

आज चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिला है। आज चांदी 800 रुपये उछलकर 75,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। जबकि चांदी बढ़त के साथ 23.70 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

आपके शहर में क्या है सोने की कीमत?

गुड रिटर्न की वेबसाइट के मुताबिक आज 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत इस प्रकार हैं:

दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,940 रुपये है।
नोएडा में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,940 रुपये है।
मुंबई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,840 रुपये है।
चैन्नई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 60,110 रुपये है।
कोलकाता में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,840 रुपये है।
बेंगलुरु में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,840 रुपये है।
केरल में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,840 रुपये है।
पटना में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,890 रुपये है।
सूरत में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,890 रुपये है।
चंडीगढ़ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 59,940 रुपये है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक शिकायत तंत्र को मजबूत करने के लिए उठाए नए कदम, RBI गवर्नर ने दी जानकारी

परिवहन विशेष न्यूज

ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा है कि केंद्रीय बैंक ने कुछ बदलाव करने और आंतरिक लोकपाल दिशानिर्देशों को एक ही मास्टर डायरेक्शन में समेकित और सुसंगत बनाने का निर्णय लिया है। चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2015 में एक आंतरिक लोकपाल (आईओ) पेश किया था।

नई दिल्ली। ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा है कि केंद्रीय बैंक ने कुछ बदलाव करने और आंतरिक लोकपाल दिशानिर्देशों को एक ही मास्टर डायरेक्शन में समेकित और सुसंगत बनाने का निर्णय लिया है।

दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि इससे विनियमित संस्थाओं की ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली और मजबूत होगी। आइए, पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्या कहा?

चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2015 में एक आंतरिक लोकपाल (आईओ) पेश किया था। इसके लेकर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौजूदा आईओ दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से मिली सीख के आधार पर इसे सुसंगत बनाने और एक समेकित मास्टर डायरेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया है।

मास्टर डायरेक्शन आईओ के पास शिकायतों को बढ़ाने के लिए समयसीमा, बहिष्करण, आंतरिक लोकपाल की अस्थायी अनुपस्थिति, आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और रिपोर्टिंग प्रारूपों के अपडेशन के अलावा उप आंतरिक के पद की शुरूआत जैसे मामलों में एकरूपता लाएगा।

एसआरओ को मान्यता देने के लिए उठाए ये कदम

उन्होंने आगे कहा, अपने सदस्यों के बीच अनुपालन संस्कृति को मजबूत करने और नीति निर्माण के लिए एक परामर्शी मंच प्रदान करने में स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) की संभावित भूमिका को देखते हुए, विभिन्न विनियमित संस्थाओं के लिए एसआरओ को मान्यता देने के लिए रिज़र्व बैंक का एक सर्वव्यापी ढांचा जारी करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि सर्वग्राही एसआरओ ढांचा व्यापक उद्देश्यों, कार्यों, पात्रता मानदंड, शासन मानकों आदि को निर्धारित करेगा, जो सभी एसआरओ के लिए समान होगा, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो। इसके अलावा रिजर्व बैंक क्षेत्र-विशिष्ट अतिरिक्त शर्तें निर्धारित कर सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे एसआरओ को मान्यता देने के लिए आवेदन मंगाने का समय आ गया है।

RBI को वापस मिले 2 हजार के 87 फीसदी नोट, बैंकों के लिए बुलेट रिपेमेंट के तहत बढ़ी गोल्ड लोन की लिमिट

आरबीआई गवर्नर ने आज मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान किया है। इस फैसले में गोल्ड लोन की लिमिट को भी बढ़ाया गया है। यह बुलेट रिपेमेंट स्कीम के तहत बढ़ाया गया है। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर ने 2000 रुपये के नोट को लेकर भी जानकारी दी है। शक्तिकांत दास ने कहा कि अभी तक 84 फीसदी नोट वापस आ गए हैं।

नई दिल्ली। आरबीआई की छह दिवसीय मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक का फैसला आज आरबीआई गवर्नर ने ऐलान किया था। इस ऐलान में दोबारा रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा आरबीआई ने महंगाई को कंट्रोल करने और जीडीपी को नियंत्रण करने के लिए भी बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने का फैसला लिया है। आरबीआई ने बुलेट रिपेमेंट स्कीम के तहत बैंकों के लिए गोल्ड लोन की लिमिट को बढ़ा दी है।

84 फीसदी लौटे 2,000 रुपये

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि अभी तक सर्कुलेशन से 2,000 रुपये के 87 प्रतिशत नोट वापस आ गए हैं। वहीं 12,000 करोड़ रुपये अभी भी वापस नहीं आए हैं।

पिछले शनिवार को आरबीआई ने कहा था कि 29 सितंबर तक 3.42 लाख करोड़ रुपये के नोट वापस आ चुके हैं। केंद्रीय बैंक ने नोट वापस करने की समयसीमा भी एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी थी। आपको बता दें कि इस साल मई में 2,000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला लिया गया था। बैंक ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि 2,000 रुपये के नोट का चलन बाजार में बाकी नोट की तुलना में कम है।

बुलेट रिपेमेंट के तहत बढ़ी गोल्ड लोन लिमिट

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट रिपेमेंट योजना के तहत गोल्ड लोन की सीमा को दोगुना कर 4 लाख रुपये करने की घोषणा की। पहले इसकी सीमा 2 लाख रुपये थे। बुलेट रिपेमेंट योजना वह है जहां एक उधारकर्ता लोन अवधि के दौरान रिपेमेंट की चिंता किए बिना लोन अवधि के अंत में ब्याज और मूल राशि चुकाता है।

बुलेट रिपेमेंट स्कीम क्या है

बुलेट रिपेमेंट योजना के तहत लोन लेने वाला मूल राशि और ब्याज का भुगतान करने के लिए एक अवधि होती है। इस अवधि के अंत में एकमुश्त कर्ज चुकाया जा सकता है। इसमें गोल्ड के बदले लोन पर ब्याज का आंकलन किया जाता है। इस तरह के रिपेमेंट को बुलेट रिपेमेंट स्कीम कहा जाता है।

त्योहारी सीजन में औंधे मुंह गिरा सोना, पिछले 10 दिन में ही 3000 रुपये की हुई गिरावट

अगर आप त्योहारी सीजन में सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। महज 10 दिनों में सोने की कीमतें करीब तीन हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर गईं। वैश्विक कारणों से दिल्ली आभूषण बाजार में सोने की कीमत में भारी गिरावट आई है। पिछले साल दिल्ली में धनतेरस पर 50 हजार करोड़ के सोने बेचे गए थे।

नई दिल्ली: त्योहारी सीजन में अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। केवल 10 दिन में ही सोने के कीमत करीब तीन हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिरी है। वैश्विक कारणों से सर्राफा बाजार में सोने के की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिल रही है।

धनतेरस में 30 प्रतिशत ज्यादा बिक्री की उम्मीद

सोने की कीमत में हुई गिरावट के कारण ज्वेलर्स इस बार के धनतेरस और दीपावली में 30 प्रतिशत से अधिक बिक्री की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनके मुताबिक दाम में कमी का सकारात्मक असर देखा जा रहा है, लोग निवेश के लिहाज से सोना खरीद रहे हैं। आपको बात दें कि कल दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,310 रुपये का था।

द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, कूचा महाजनी के चेयरमैन योगेश सिंघल ने कहा कि दिल्ली में पिछले साल धनतेरस पर दिल्ली के ज्वेलरी बाजारों में 45 हजार से 50 हजार करोड़ रुपये के सोने की बिक्री हुई थी।

वायदा बाजार में आज सोना

वायदा कारोबार में आज सोने की कीमत 29 रुपये बढ़कर 56,637 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 29 रुपये या 0.05 प्रतिशत बढ़कर 56,637 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 16,194 लॉट का कारोबार हुआ।

वायदा कारोबार में चांदी

आज वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 157 रुपये बढ़कर 66,925 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 157 रुपये या 0.24 प्रतिशत बढ़कर 31,718 लॉट में 66,925 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।

क्या है आज के गोल्ड के रेट?

गुड रिटर्न वेबसाइट के मुताबिक खबर लिखे जाने तक

चेन्नई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,650 रुपये है।
दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,380 रुपये है।
मुंबई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,230 रुपये है।
कोलकाता में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,230 रुपये है।

लोन की किस्त सस्ती होने का था इंतजार तो जानें RBI के फैसले का क्या होगा असर, यहां पढ़ें मुख्य बातें

भारतीय रिजर्व बैंक के तीन दिवसीय बैठक का फैसला आज आ गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान किया है। इस बैठक में भी Repo Rate को स्थिर रखने का फैसला लिया गया है। रेपो रेट का सीधा असर Loan पर पड़ता है। आइए इस बैठक में लिए गए फैसलों की मुख्य बातों के बारे में जानते हैं।

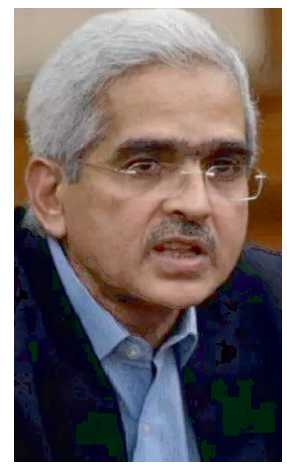

नई दिल्ली। RBI MPC MEET 2023 Big Update: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज सुबह एमपीसी बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान किया है। इन फैसलों का असर भारत की अर्थव्यवस्था के साथ ही आपके बजट पर भी पड़ेगा। इस बैठक में सबकी नजर रेपो रेट पर रहती है। आइए, इस बैठक में लिए गए फैसलों की मुख्य बातें जानते हैं।

नई मौद्रिक नीति की मुख्य बातें

आरबीआई ने इस बैठक में भी रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया है। इसका मतलब है कि रेपो दर 6.5 फीसदी पर स्थिर है। वहीं एसडीएफ (SDF) रेट 6.25 फीसदी पर बरकरार है और एनसीएफ (MSF) दर और बैंक दर 6.75 फीसदी पर बरकरार है।

आरबीआई ने 'Withdrawal Of Accommodation' नीति को अपनाया है। बैंक महंगाई को नियंत्रित करने पर कार्य कर रही है।

आरबीआई ने भारत की जीडीपी को लेकर कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 फीसदी से बढ़ सकती है।

वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही देश की जीडीपी 6.5 फीसदी हो सकती है। वहीं, तीसरी और चौथी तिमाही 5.7 फीसदी हो सकती है। इसी तरह अगले चालू वित्त वर्ष 2024-24 के पहले तिमाही में जीडीपी 6.6 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है।

आरबीआई ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में CAPEX बढ़ा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार देखने को मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन गतिविधियों में तेजी आई है।

ग्लोबल आउटलुक ने महंगाई दरों को प्रभावित किया है। इस साल जुलाई में सब्जियों की कीमत में तेजी देखने को मिली है।

आरबीआई गवर्नर ने 2024 में महंगाई दर 5.4 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।

वहीं सीपीआई (CPI) दर के बारे में कहा कि इस तिमाही यह 6.4 फीसदी था। जो चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 5.6 फीसदी और चौथी तिमाही और अगले चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5.32 फीसदी रह सकती है।

गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश में बैंकिंग सिस्टम मजबूती से कायम है। इसके आगे वह कहते हैं कि लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) सेल्स संभव हो सकती है। वहीं, SDF और VRRR को स्थिर रखा जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय स्थिरता पर फोकस कर रहा है। वह बैंक, NBFCs पर निगरानी सिस्टम को मजबूत कर रहा है। इसके अलावा बैंक पर्सनल लोन में आए उछाल पर भी ध्यान दे रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जानकारी दी कि 29 सितंबर 2023 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 58,690 करोड़ डॉलर था।

दालों की खेती में कमी और सप्लाई के दबाव की वजह से जुलाई में महंगाई बढ़ी है। आने वाले समय में महंगाई कम होने की संभावना है।

FY24 में 5.4 प्रतिशत पर ही महंगाई के रहने का अनुमान, सितंबर में कम रह सकती है खुदरा मुद्रास्फीति

एमपीसी की बैठक में नतीजों की घोषणा करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2023-24 के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को 5 .4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। इसके अलावा आरबीआई यह भी सुनिश्चित करता है कि वह वैश्विक खाद्य और ईंधन की कीमतों में झटके से बचने के लिए समय पर उचित उपाय करेगा। पढ़िए क्या है पूरी खबर।

नई दिल्ली: RBI MPC Meeting Update। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज एमपीसी की बैठक में लिए गए नतीजों को सुनाते हुए 2023-24 के लिए मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को 5.4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।

इसके अलावा आरबीआई ने यह भी आश्वासन दिया कि वैश्विक खाद्य और ईंधन की कीमतों के किसी भी झटके को रोकने के लिए समय पर पर्याप्त कदम उठाया जाएगा।

सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति कम रहने की उम्मीद

गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सितंबर की खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े अगस्त और जुलाई से कम हो सकती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित सकल मुद्रास्फीति 2023-24 की पहली तिमाही में कम होकर 4.6 प्रतिशत हो गई थी जो एक साल पहले इसी अवधि में 7.3 प्रतिशत थी।

क्या है आरबीआई का अनुमान?

आरबीआई ने 2023-24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है। तिमाही दर तिमाही की बात करें तो दूसरी तिमाही में आरबीआई ने सीपीआई मुद्रास्फीति 6.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

वहीं अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 की पहली तिमाही के लिए आरबीआई ने सीपीआई मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

आगमी समय में कम हो सकती है मुद्रास्फीति

आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि सब्जियों, खासकर टमाटर की कीमतों में सुधार और एलपीजी की कीमतों में कमी के कारण निकट अवधि में मुद्रास्फीति में नरमी की उम्मीद है। इसके अलावा मुद्रास्फीति में नरमी कैसी रहेगी यह विभिन्न कारणों जैसे अल नीनो, डिमांड और सप्लाई, खरीफ फसल के पैदावार पर निर्भर करता है।

जीडीपी का अनुमान 6.5 प्रतिशत पर बरकरार

आज एमपीसी के फैसलों को सुनाते हुए शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। इसके अलावा आरबीआई ने आज रेपो रेट को भी 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।

यह लगातार चौथी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है। आखिरी बार रेपो रेट को फरवरी 2023 में 0.25 प्रतिशत बढ़ाया गया था। दरअसल मई 2022 से आरबीआई ने रेपो रेट को फरवरी 2023 तक बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत तक कर दिया है।

8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है Jio Utsav Celebration of India, महेंद्र सिंह धोनी बने JioMart के ब्रांड एंबेसडर

देश के मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी अब रिलायंस रिटेल के जियोमार्ट के ब्रांड एंबेसडर बन गए हैं। वह जल्द ही 45 सेकेंड की फिल्म में नजर आएंगे। आपको बता दें कि जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया 8 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाला है। जियोमार्ट के सीईओ संदीप वरागंती धोनी का स्वागत किया और उन्हें मधुबनी पेंटिंग भेंट की।

नई दिल्ली। रिलायंस रिटेल के जियोमार्ट ने भारतीय क्रिकेट आइकन महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है। इसके अलावा जियोमार्ट ने अपने फेस्टिव कैंपेन का नाम भी बदल दिया है। अब इसका नाम 'जियो उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया' कर दिया है। आपको बता दें कि यह फेस्टिव कैंपेन सेल 8 अक्टूबर, 2023 से शुरु होगी।

महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि

भारत अपनी जीवंत संस्कृति, लोगों और त्योहारों के लिए जाना जाता है, जियोमार्ट का 'जियो उत्सव कैंपेन' भारत और उसके लोगों के उत्सव का एक प्रतीक है। मैं जियोमार्ट के साथ जुड़ने और लाखों भारतीयों की खरीदारी यात्रा का हिस्सा बनने पर बेहद उत्साहित हूं।

धोनी बने ब्रांड एंबेसडर

धोनी को जियोमार्ट का ब्रांड एंबेसडर बनने पर जियोमार्ट के सीईओ संदीप वरागंती ने स्वागत किया है। उन्होंने इस कैंपेन से जुड़ने पर धोनी को बिहार की कारीगर अंबिका देवी द्वारा बनाई गई एक मधुबनी पेंटिंग भेंट की। आपको बता दें कि ब्रांड एंबेसडर के तौर पर धोनी 45 सेकेंड की फिल्म में नजर आएंगे।

संदीप वरागंती ने कहा कि

ब्रांड एंबेसडर के रूप में एमएस धोनी एकदम सटीक पसंद हैं, उनका व्यक्तित्व जियोमार्ट की तरह ही विश्वसनीय है। धोनी ने देश को जश्न मनाने के कई मौके दिए हैं, और अब ग्राहकों को जियोमार्ट पर जश्न मनाने का एक और मौका मिल रहा है और 'शॉपिंग' इस जश्न का एक अभिन्न अंग है।

जियोमार्ट के बारे में

जियोमार्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फैशन और सौंदर्य के अलावा घरेलू सजावट के सामान भी उपलब्ध है। इसमें अर्बन लैडर, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस ज्वेल्स, हैमलीज़ सहित रिलायंस के भी ब्रांड के प्रोडक्ट शामिल है।

आपको बता दें कि जियोमार्ट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। वर्तमान में इसके 1000 से अधिक कारीगर हैं। जो करीब 1.5 लाख प्रोडक्ट बेच रहे हैं।

बहुत जल्द ओड़िशा मे देखेंगा मेट्रो ट्रेन

मनोरंजन सासमल , ओड़िशा

भुबनेस्वर : बहुत जल्द स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर मेट्रो ट्रेन। परियोजना की डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है क्योंकि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस डीपीआर को मंजूरी दे दी है. हालांकि, मिली जानकारी के आधार पर माना जा रहा है कि जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी.यह कार्य 'टर्न की' आधार पर करने का निर्णय लिया गया है। भुवनेश्वर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने निर्देश जारी किए हैं कि योग्य संगठन टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। मालूम हो कि भुवनेश्वर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की पहली बोर्ड बैठक अगले महीने की 18 तारीख को होने जा रही है. बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे. परिवहन सचिव, वित्त सचिव, शहरी विकास विभाग सचिव, बंदरगाह सचिव और बीएमआरसी के अध्यक्ष सदस्य हैं। हालांकि, बैठक में डीपीआर की मंजूरी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार मेट्रो प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपये खर्च करेगी. शुरुआती चरण में इस प्रोजेक्ट के लिए 210 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट रखा गया है. मेट्रो प्रोजेक्ट अगले 4 साल में पूरा होने की उम्मीद है. और ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इसके लिए बीएमआरसी को हर साल 15 सौ करोड़ रुपये का भुगतान करेगी. हालाँकि, उम्मीद है कि इस मेट्रो ट्रेन परिचालन से भुवनेश्वर में बढ़ती यातायात समस्या सहित विभिन्न स्थानों पर नौकरी करने वाले लोगों और छात्रों को मदद मिलेगी ।जहां इसे मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, वहीं ओडिशा की योजना इस परियोजना को कुछ ही दिनों में पूरा कर एक मील का पत्थर स्थापित करने की है।

सुपार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर हाउसिंग बोर्ड में

मुनि आदित्य सागर संघ का सुपार्श्वनाथ मंदिर में होगा मंगल प्रवेश स्वागत

अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। सुपार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर हाऊसिंग बोर्ड में वार्षिक कलशाभिषेक समारोह दिनांक 08 अक्टूम्बर रविवार को दोपहर 2.00 बजे से प्रेम चुनरिया सुपार्श्वनाथ चौराहा हाउसिंग बोर्ड में कार्यक्रम प्रारम्भ हो जायेगें। समिति के अध्यक्ष राकेश पाटनी ने बताया कि तप आराधना करने वाले तपस्वियों का, 80 वर्ष से ऊपर वाले बुजुर्गों का, जैन पाठशाला के छात्रों का, तथा समाज में उत्कृष्ठ कार्य करने वालों का सम्मान किया जायेगा। कार्यक्रम के पश्चात भगवान का अभिषेक मुनिसंघ के सानिध्य में दोपहर 4 बजे होगा।

मीडिया प्रभारी भागचन्द पाटनी ने बताया कि मुनि आदित्य सागरजी ससंघ प्रातः 7 बजे चन्द्रशेखर आजाद नगर से विहार कर रामधाम से अरिहंत हॉस्पिटल होते हुए शास्त्रीनगर, ब्राहारणी स्वीट्स से प्रेम चुनरिया सुपार्श्वनाथ सर्किल से प्रातः 8.30 बजे सुपार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में मंगल प्रवेश करेगें। रास्ते में जगह-जगह स्वागत हेतु स्वागत द्वार बनाये जा रहे है। अरिहंत हॉस्पिटल से सुपार्श्वनाथ मंदिर तक बैण्ड-बाजों के साथ शोभायात्रा निकाली जायेगी। जिसका संचालन सुपार्श्वनाथ जागृति मंच के तत्वाधान में होगा। रास्ते में स्वागत हेतु जगह-जगह श्रावकों द्वारा मुनि संघ का पाद प्रक्षालन किया जायेगा। प्रेम चुनरिया के सामने सुपार्श्वनाथ सर्किल पर 51 थालियों से पाद प्रक्षालन कर एवं फूल वर्षा कर स्वागत किया जायेगा। जिसकी तैयारियों जोरों पर है। इस हेतु श्रावक-श्राविकाओं में काफी उत्साह है।

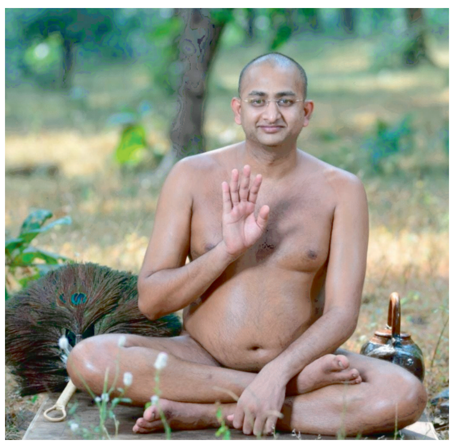

पांच राज्यों में चुनाव की धोषणा शीघ्रः सूत्र

परिवहन विशेष। एसडी सेठी। नेताओ की सांस थमने का वक्त आ गया है। क्योंकि शुक्रवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में चुनाव आयोग की मीटिंग में पांच राज्यों के चुनाव को लेकर खाका तैयार कर लिया गया है। प्रवेक्षकों की टीमें आज ही तेलांगना को छोडकर अन्य चार राज्यों का दौरा कर दिल्ली लौटी है। उनके लौटते ही पांच राज्यों के चुनाव पर खाका तैयार कर लिया गया है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूतों के मुताबिक नवंबर के दूसरे हफ्ते और दिसंबर के पहले हफ्ते के बीच 5 राज्यों में चुनाव कराए जा सकते है ।चुनाव की तारीख को लेकर दिल्ली में प्रवेक्षकों की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अलावा दोनों चुनाव आयुक्त भी शामिल थे। साथ ही जनरल ऑब्जर्वर एक्सपेंडीचर और सिक्योरिटीज ऑब्जर्वर भी मौजूद थे। बता दें मिजोरम का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है ।वहीं तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ और राजस्थान का कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म होगा। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ में 2 चरणों में और बाकी तेलंगाना, राजस्थान, मध्यप्रदेश, मिजोरम के एक चरण में होगे। सूत्रों के मुताबिक मतगणना 10-15 दिसंबर को हो सकती है। वहीं रविवार तक हो सकता है चुनाव का ऐलान।

दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन के पास हुई दुर्घटना, पटरी से उतरी मालगाड़ी; ट्रेनों का बदला रूट

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के नजदीक एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ लेकिन इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई है। रेलवे दुर्घटना के कारण की जांच के लिए समिति गठित कर दी है। शुक्रवार दोपहर 12 .50 बजे हजरत निजामुद्दीन व लाजपतनगर के बीच एक मालगाड़ी के पांच वैगन पटरी से उतर गए।

नई दिल्ली। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के नजदीक एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई है। रेलवे दुर्घटना के कारण की जांच के लिए समिति गठित कर दी है। शुक्रवार दोपहर 12.50 बजे हजरत निजामुद्दीन व लाजपतनगर के बीच एक मालगाड़ी के पांच वैगन पटरी से उतर गए। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों ने अधिकारियों को सूचित किया।

जब मौके पर पहुंचे अधिकारी

दिल्ली के डीआरएम सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस दुर्घटना से हजरत निजामुद्दीन से गाजियाबाद को जोड़ने वाली अप एवं डाउन दोनों लाइन बाधित हो गई। समाचार लिखे जाने तक इससे ट्रेनों की आवाजाही शुरू नहीं हुई थी।

इन ट्रेनों का बदला गया समय

दुर्घटना के कारण देहरादून-इंदौर एक्सप्रेस (14318) और चंडीगढ़ मदुरै एक्सप्रेस (12688) के मार्ग में बदलाव कर साहिबाबाद, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली-हजरत निजामुद्दीन के रास्ते चलाया गया। वहीं, नई दिल्ली-पानीपत महिला विशेष (04963), नई दिल्ली पलवल ईएमयू (04966), हजरत निजामुद्दीन कुरुक्षेत्र विशेष (04405) निरस्त कर दी गईं।

बीजेपी द्वारा पोस्टर में राहुल को रावण पर बवाल

परिवहन विशेष। एसडी सेठी। चुनावों की बढती सरगर्मी के बीच सभी दलों में जुबानी,पोस्टर बाजी-तल्खियां सामने आने लगी है। इसी कडी में बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दशानन के रूप में दर्शाते हुए ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की और उन्हें ' नए युग का रावण करार दिया । उन्हें , धर्म विरोधी, राम-विरोधी, लिखकर बताया कि ,उनका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। ग्राफिक के माध्यम से फिल्मी पोस्टर तैयार कर इस तस्वीर के उपर लिखा गया है 'भारत खतरे में है। साथ ही राहुल गांधी की तस्वीर पर 'रावण' तथा तस्वीर के के हिस्से में 'ए' कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन और जार्ज सोर्स एक अमेरिकी अरबपति है और भाजपा उस पर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने का आरोप लगाती रही है। भाजपा के इस पोस्टर से कांग्रेस कार्यकर्ताओ में उबाल ला दिया। उन्होंने भाजपा कार्यालय के बाहर जमकर बवाल काटा। कांग्रेस कार्यकर्ताओ पर पुलिस बल ने पानी की बौछार कर पीछे हटने को मजबूर कर दिया ।इस पर जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो आपको एक बार फिर झुकने पर मजबूर कर देगा ।क्योंकि' भारत में सदैव सत्यमेव जयते' की जीत हुई है।

देशभर के ईएसआई अस्पतालों में 8 साल से लंबित 7वां वेतन आयोग लागू

परिवहन विशेष। एसडी सेठी। देशभर के ईएसआईसी अस्पतालों के मेडिकल लैबोरेट्रीज टेक्नॉलिजिस्टों की इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है ।उनको पिछले आठ साल से 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया था। 5 अक्टूबर को भारत सरकार ने इस बावत आर्डर जारी कर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशो को फाईल नंबर / ए-12011/5/2021-एमइडी-VI तिथि 5 अक्टूबर 2023 को लागू कर दिया है। इस बावत मेडिकल लैबोरेट्रीज टेक्नॉलिजिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील सरकनिया ने बताया कि यूनियन ने पिछले 8 साल से लगातार संघर्ष जारी रखा। उन्होंने कहा कि सभी लैबोरेट्रीज टेक्नॉलिजिस्ट के सघर्ष के परिणाम स्वरूप सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ उन्हें मिल सकेगा। इस मौके पर एसोसिएशन के सेंट्रल जोन के सदस्य सुनील सरकनिया ,इंद्राणी कुमारी,विनेश देशराम, किशोर केरकटा समेत तमाम लैबोरेट्रीज टेक्नॉलिजिस्ट भी मौजूद थे।

भीलवाडा में बनेगा विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाने का विश्व कीर्तिमान

2000 मिट्टी की ईटो 1000 किलो कोयला की भट्टी 1000 किलो के तवे से बनेगी विश्व की सबसे बडी रोटी

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा । महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी हंसराम जी उदासीन के आशीर्वाद पावन सानिध्य में भाजपा जिला प्रवक्ता राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी के जन्मदिन के उपलक्ष में एक अनूठा अद्भुत अकल्पनीय रोमांचित करने वाला सनातन संस्कृति को आगे बढ़ने वाला विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाने का विश्व रिकॉर्ड हरी सेवा धाम परिसर में 8 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा इस विशालकाय रोटी को विशालकाय स्टील के डंडे लगभग 20 फीट लंबे से बेला जाएगा और इस रोटी को ऊपर से सेकने के लिए रोटी के ऊपर भी तवा लगाकर सिकाई कि जाएगी इस कार्यक्रम की लाइव रिकॉर्डिंग भी की जाएगी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए लिम्का बुक का रिकॉर्ड इंटरनेशनल बुक का रिकॉर्ड मे भी आवेदन कर दिया है , इसके बाद रोटी ओर पंचकुटा की सब्जी को प्रसाद के रूप में उस दिन आने वाले हजारों श्रद्धालुओं भक्तों आमजन मे वितरित किया जाएगा

विदित रहे की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था वर्ष 2012 में जिसमें विश्व की सबसे बड़ी रोटी का निर्माण किया गया था जिसका वजन 145 किलो था इस रोटी का व्यास 10 फिट गुणा 10 फिट का थाअब इस विश्व रिकार्ड को तोड़ने एवं नया विश्व रिकॉर्ड कायम करने की कवायद प्रारंभ हो गई है और 8 अक्टूबर को भीलवाड़ा शहर में नया विश्व कीर्तिमान बनेगा इस विश्व रिकॉर्ड के तहत 151 किलो से अधिक की रोटी जिसका व्यास 11x11 फीट को होगा इसकी मोटाई लगभग 70 एम एम की होगी इसको बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का विशालकाय तवा तैयार किया जाएगा जिसकी लंबाई चौड़ाई 16 फीट x 12 फीट की होगी इसको तैयार करने के लिए विशेष कारीगर को बुलाया जाएगा साथ ही इस रोटी को बनाने के लिए हलवाइयों की टीम रहेगीइस विशालकाय रोटी को देखने के लिए भीलवाड़ा शहर वीडियो में जबरदस्त उत्साह रोमांच और विशेष कर महिलाओं युवतियों मे बहुत अधिक उत्सुकता है हजारों लोगों की भीड़ इस दिन रहेगी।

पंजाब सरकार द्वारा भगवान वाल्मीकि तीर्थ श्राइन बोर्ड में वाल्मीकि समाज को दरकिनार करने व सफाई कर्मचारीयो की स्थाई नौकरीयो के लिए लागू किए गए रोस्टर के विरुद्ध भगवान वाल्मीकि आश्रम धूना साहिब ट्रस्ट और सफाई मजदूर फेडरेशन

अमृतसर (साहिल बेरी) पंजाब आगामी 9 को अक्टूबर तीन दिन के लिए भंडारी पुल पर चक्का जाम करेगा। पत्रकारों से बातचीत करते ट्रस्ट के चेयरमैन ओम प्रकाश गब्बर व गुरु ज्ञान नाथ वाल्मीकि धर्म समाज संगठन के मुख्य संचालक नछत्तर नाथ शेरगिल ने कहा कि सरकार ने उनसे वायदा खिलाफी कर उनकी कमर में छुरा गोप दिया। श्राइन बोर्ड भंग करने की बजाय बोर्ड कमेटी में वाल्मीकि समाज को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। उन्हें कहा कि 9 अक्टूबर को ट्रस्ट के गद्दी नशीन संत मसकीन नाथ की अध्यक्षता में पूरे पंजाब से वाल्मीकि समाज के लोग भंडारी पुल पर पहुंचेंगे और अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर अमरदीप सिंह, धीर सिंह, दिदार सिंह, धर्मेंद्र सिंह, रुपस मट्टू, महेंद्र सिंह सरपंच आदि उपस्थित थे।

हमारी पार्टी ईमानदारी की बुनियाद पर खड़ी है, संजय सिंह और मनीष सिसौदिया जैसे लोग नेता नहीं, आम जनता के सच्चाई के सिपाही हैं:- कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल

अमृतसर (साहिल बेरी) आप नेताओं से डरती है बीजेपी, बोले-सीबीआई-ईडी और पुलिस आगेः - कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने केंद्र सरकार के खिलाफ सीबीआई-ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के नेतृत्व में भंडारी पुल पर आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका मीडिया को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी संजय सिंह और मनीष सिसौदिया जैसे नेताओं की नहीं बल्कि आम जनता की ईमानदारी की बुनियाद पर खड़ी है. बहिष्कृत लोग सत्य के सिपाही हैं। वे ईडी से नहीं डरते. सुप्रीम कोर्ट भी यही सवाल पूछ रहा है कि सबूत लाओ लेकिन आज तक ईडी और सीबीआई हमारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है. कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जी को राज्यसभा में बीजेपी के खिलाफ बोलने के कारण राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है और ईडी छापेमारी करके उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रही है। भाजपा को अपनी लोक नौटंकी बंद करनी चाहिए अमृतसर शहर अध्यक्ष मुनीष अग्रवाल और ग्रामीण अध्यक्ष कुलदीप सिंह मथरेवाल ने संयुक्त रूप से कहा कि भाजपा निराशा की स्थिति में है क्योंकि लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता का ग्राफ दिन-ब-दिन गिरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नौ साल से अधिक समय से केंद्र में है। अब उन्हें नफरत की राजनीति, पूंजीपतियों का प्यार और जनविरोधी नीतियां महसूस हो रही हैं। इसलिए वे लगातार अपने खिलाफ बोलने वाले को डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 98117320995.
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023